

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शुक्रवार 12 सितंबर 2025 वर्ष-8,अंक-203 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रुपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अमेरिका: छात्रों के सवालों के जवाब दे रहे किर्क की गोली मारकर हत्या, शोक में झुके झंडे



वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और कंजर्वेटिव एडिटरविस्ट और टर्निंग प्वाइंट यूएसए के को-फाउंडर चार्ली किर्क (31) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना उस तक हुई जब किर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी, ओरेगन में छात्रों के सवालों के जवाब दे रहे थे। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई और वे मंच पर गिर पड़े। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। चार्ली किर्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खास लोगों में से एक थे। शोक में अमेरिकी झंडे झुकाए गए। घटना के तुरंत बाद स्वात टीम, एटीएफ पुलिस और अन्य एजेंसियों ने कैंपस को लॉकडाउन कर तलाशी अभियान चलाया। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया था कि पुलिस ने एक सदिग्ध को पकड़ा है, लेकिन बाद में अधिकारियों ने साफ किया कि असली हमलावर अभी फरार है।

छत्तीसगढ़ में बड़ा एनकाउंटर, 10 नक्सली ढेर, 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण भी मारा गया

वाशिंगटन (एजेंसी)। सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में गुरुवार को एक मुठभेड़ के दौरान शीर्ष माओवादी कमांडर मोडेम बालकृष्ण उर्फ मनोज समेत 10 नक्सलियों को मार गिराया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हालांकि, मुठभेड़ अभी भी जारी है, इसलिए संख्या बढ़ने की उम्मीद है। मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए, रायचूर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा ने बताया कि क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान मेनपुर थाना क्षेत्र के जंगल में मुठभेड़ शुरू हुई। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ), कोबरा (सीआरपीएफ) की एक विशिष्ट इकाई - कमांडो बटालियन फोर रेजोयूट्युट वक्शन) और अन्य राज्य पुलिस इकाइयों के जवान इस अभियान में शामिल हैं। अभी भी रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है। सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों के खिलाफ कई अभियान चलाए हैं। गौरतलब है कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी आतंकवाद को खत्म करने का लक्ष्य 31 मार्च, 2026 रखा है। इससे पहले, नारायणपुर जिले में विभिन्न इकाइयों के निचले स्तर के 16 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया। पुलिस के अनुसार, नक्सली खोखली माओवादी विचारधारा और उनके द्वारा निंदीय आदिवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों से निराश थे। पुलिस अधिकक्ष के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि वे (शीर्ष माओवादी नेता) स्थानीय लोगों को जल, जंगल और जमीन की रक्षा, समानता और न्याय के झूठे वादों से गुमराह करते हैं, और उनका शोषण और उन्हें गुलाम बनाते हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं को गंभीर शोषण का सामना करना पड़ता है, और महिला माओवादियों की स्थिति और भी बदतर है।

ऐश्वर्या राय को मिली दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, उनके नाम और फोटो के गलत इस्तेमाल पर लगाई रोक

नई दिल्ली (एजेंसी)। बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत ने उनके नाम, फोटो और पहचान के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाते हुए कई संस्थाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस तेजस करिया की एकल पीठ ने कहा, कि ऐश्वर्या राय के नाम और छवि का बिना अनुमति इस्तेमाल उनकी निजता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी माना कि इस तरह की गतिविधियां अभिनेत्री की साख, प्रतिष्ठा और आर्थिक हितां को नुकसान पहुंचा सकती हैं और लोगों को गुमराह कर सकती हैं कि वह किसी उत्पाद या सेवा का समर्थन करती हैं। अदालत ने उनके पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की और अज्ञात पक्षों समेत सभी प्रतिवादियों को उनके नाम ऐश्वर्या राय बच्चन, संक्षिप्त नाम 'एसएबी', फोटो, समानता और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं के उपयोग से वाणिज्यिक या व्यक्तिगत लाभ उठाने पर रोक लगा दी। यह आदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीपफेक, फेस माफ़िंग और मशीन लर्निंग सहित सभी तकनीकों पर लागू होगा। कोर्ट ने गूगल एलएलसी को निर्देश दिया कि वह मुकदमे में उल्लिखित यूआरएल को 72 घंटों के भीतर हटाए और उन वेबसाइट संचालकों की जानकारी सीलबंद रूप में उपलब्ध कराए। साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सात दिनों के भीतर विवादित यूआरएल ब्लॉक करने का आदेश दिया गया।

सोनिया गांधी के खिलाफ याचिका खारिज... नागरिकता से पहले मतदाता सूची में नाम जुड़ने तक रुक

नई दिल्ली (एजेंसी)। (, (इंएमएस)। दिल्ली की राजन एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत को खारिज किया है, इसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी नागरिकता प्राप्त करने से पहले उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हुआ था। मामले में एक वकील द्वारा दायर याचिका को कोर्ट ने अस्वीकार किया, जिसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।

शिकायतकर्ता वकील ने दावा किया कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता प्राप्त की, लेकिन उनके नाम को 1980 की दिल्ली मतदाता सूची में शामिल था।

मारिशस और भारत सिर्फ पार्टनर नहीं एक परिवार हैं

वाराणसी(एजेंसी)। मॉरिशस के प्रधानमंत्री खं नवीन चंद रामगुलाम एवं नरेंद्र मोदी नें संयुक्त रूप से आज 11 सितंबर, 2025 को प्रेस वार्ता की और मीडिया को सम्बोधित किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नें कहा कि मेरे लिए गर्व का विषय है कि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। चिर काल से काशी भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक रही है।

हमारी संस्कृति और संस्कार, सदियों पहले भारत से मॉरिशस पहुँचे, और वहाँ की जीवन-धारा में रच-बस गए। काशी में माँ गंगा के अविरल प्रवाह की तरह, भारतीय संस्कृति का सतत प्रवाह मॉरिशस को समृद्ध करता रहा है। और आज,जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं, बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं, बल्कि एक परिवार हैं।

मॉरिशस, भारत की Neighbourhood

प्रधानमंत्री ने किया देहरादून का दौरा, उत्तराखंड में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक की पीएम मोदी ने उत्तराखंड में बाढ़ के लिए 1200 करोड़ रु की वित्तीय सहायता की घोषणा की

कोलकाता (एजेंसी)। नई दिल्ली (इंएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून का दौरा किया और उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों में बादल फटने, बारिश और भूस्खलन के कारण बाढ़ की स्थिति और नुकसान की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा और नुकसान का आकलन करने के लिए देहरादून में एक आधिकारिक बैठक की। उन्होंने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की।

प्रधानमंत्री ने पूरे क्षेत्र और उसके लोगों की मदद के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत



First नीति और Vision 'महासागर' का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने अपने संबंधों को 'Enhanced Strategic Partnership' का दर्जा दिया। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय

और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए।

मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चांगोस समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। ये मॉरिशस की संप्रभुता की एक ऐतिहासिक जीत है। भारत ने हमेशा decolonization, और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है। और इसमें

भारत, मॉरिशस के साथ दृढ़ता से साथ खड़ा रहा है।

मॉरिशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक Special Economic Package पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर, पहला जनऔषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में AYUSH Centre of E&cellence, 500-बेड का Sir Seewoosagur Ramgoolam नेशनल हॉस्पिटल; और Veterinary School and Animal Hospital के निर्माण में भारत सहयोग देगा। साथ ही हम चांगोस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया; स्क्रू इंटनेशनल एयरपोर्ट के ATC टावर; तथा हाईवे और रिंग रोड के विस्तार जैसी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे।

अमित शाह ने किया फास्ट ट्रेक इमीग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का उद्घाटन



नई दिल्ली (एजेंसी)। केन्द्रीय

गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कोझिकोड और अमृतसर हवाईअड्डे पर फास्ट ट्रेक इमीग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि इस सुविधा से न सिर्फ प्रवासियों की सुविधा बढ़ेगी बल्कि हमें देश में होने वाले परिवर्तनों से उनका परिचय कराने का भी मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वप्न - स्पीड, स्केल और स्कोप - को इस प्रोग्राम में समाहित कर प्रवासियों की सुविधा को बढ़ाने के प्रयास का अगला चरण आज से शुरू हो रहा है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि तकनीकी दृष्टि से साथ-साथ हमें एक ट्रस्ट मल्टीप्लायर का काम भी करना चाहिए और आज का कार्यक्रम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अमित शाह ने कहा कि फास्ट ट्रेक

इमीग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम के साथ आज से हवाईअड्डों पर सीमलेस इमीग्रेशन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ सुविधा देने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा बल्कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिक से अधिक यात्रियों को इसका फायदा मिले। इसके लिए पासपोर्ट और ओसीआई काई जारी करते समय ही हमें रजिस्ट्रेशन करने की संभावना पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो यात्रियों को दोबारा फिंगरप्रिंट और दस्तावेजों के लिए आने की जरूरत नहीं रहेगी और वे जब भी यात्रा करना चाहें तो पासपोर्ट का उपयोग कर सकेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि इस बारे में सभी तकनीकी संभावनाओं को तलाश कर हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकतम लोगों को इसका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय नागरिकों के साथ-साथ ओसीआई कार्डधारकों को भी फायदा होगा।

रायबरेली में फिर बोले राहुल गांधी- हाइड्रोजन बम आएगा, सब साफ हो जाएगा



रायबरेली (एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में एक बार फिर वोट चोरी पर तीखा बयान देकर राजनीतिक माहौल को गर्मी का काम कर दिया है। बचत भवन में आयोजित दिशा की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, कि बीजेपी को ज्यादा एजिटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बम आने वाला है और जब वह आएगा तो सब साफ हो जाएगा।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया, कि देशभर में वोट चोरी, गद्दी छेड़ का नारा आग की तरह फैल रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को यह समझना होगा कि वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं। विपक्ष के नेता ने आगे कहा, कि हम गारंटी के साथ आपको प्रूफ देने वाले हैं। बैंगलुरु सेंट्रल में हमने ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिए हैं। आने वाले समय में एक और विस्फोटक सबूत आपके सामने रखेंगे। उन्होंने बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन

विवाद का जिक्र करते हुए कहा, कि सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में भी वोट चोरी की घटनाएँ हुई हैं।

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को दो दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। कल उनके आगमन पर एक मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। यूपी सरकार के मंत्री विदेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में पार्टी समर्थक कार्यकर्ता सड़क पर धरना देकर बैठ गए और राहुल गांधी से प्रश्नांतर मंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ कथित अपशब्दों के लिए माफी की मांग की। इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई।

फिलहाल राहुल गांधी के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी ने उन पर बेतुकी बातें करने और प्रूफ देने वाले हैं। बैंगलुरु सेंट्रल में हमने ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिए हैं। आने वाले समय में एक और विस्फोटक सबूत आपके सामने रखेंगे। उन्होंने बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन

तीनों सेनाओं की महिला जल यात्रा ‘समुद्र प्रदक्षिणा’ को रक्षा मंत्री ने हरी झंडी दिखाई - दस महिला अधिकारी अगले 9 महीनों में लगभग 26 हजार समुद्री मील की यात्रा करेंगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पहली बार तीनों सेनाओं की महिला जल यात्रा ‘समुद्र प्रदक्षिणा’ गुरुवार को मुंबई से शुरू हुई, जिसमें 10 महिला अधिकारी अगले 9 महीनों में स्वदेशी नौकायन पोत त्रिवेणी पर सवार होकर लगभग

26 हजार समुद्री मील की यात्रा करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस नौकायन अभियान को वचुंअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से रवाना किया। राजनाथ सिंह ने इस यात्रा को नारी शक्ति, सशस्त्र बलों की एकता, आत्मनिर्भर भारत और भारत की सैन्य कृत्नीति एवं वैश्विक दृष्टिकोण का ज्वलंत प्रतीक बताया है।

नारी शक्ति और विकासित भारत के विजन को स्मरण करते हुए रक्षा मंत्री ने साउथ ब्लॉक से अपने संबोधन में कहा कि इस अभियान के दौरान महिला अधिकारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प की लौ अंधकार को चीरती रहेगी। वे सुरक्षित घर लौटेंगी और दुनिया को दिखाएंगी कि भारतीय महिलाओं का पराक्रम किसी भी सीमा



से परे है।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगले नौ महीनों में 10 महिला अधिकारी स्वदेश निर्मित भारतीय सेना नौकायन पोत (आईएसवी) त्रिवेणी पर सवार होकर पूर्वी मार्ग पर लगभग 26 हजार समुद्री मील की यात्रा करेंगी। वे भूमध्य रेखा को दो बार पार करेंगी और तीन महान अंतर्राीय लीज्वन, हॉर्न और गुड होप का चक्कर लगाएंगी। इस दौरान वे सभी प्रमुख महासागरों और दक्षिणी

नितिन गडकरी ने ई20 ईंधन पर ‘पेट्रोल लॉबी’ के दुष्प्रचार को बताया निराधार

नई दिल्ली। (केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ई20 ईंधन को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे विवाद को ‘पेट्रोल लॉबी’ द्वारा प्रायोजित दुष्प्रचार करार दिया। ई20 ईंधन में 80 प्रतिशत पेट्रोल और 20 प्रतिशत एथेनॉल होता है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर यह चिंता जताई गई कि ई20 ईंधन से वाहन की माइलेज और इंजन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गडकरी ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि पेट्रोल लॉबी बहुत मजबूत और अमीर है और वह ईंधन के खिलाफ गलत प्रचार कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह दुष्प्रचार निराधार है और पेट्रोलियम मंत्रालय भी ईंधन दक्षता में कमी की आशंकाओं को गलत मानता है। मंत्री ने भारतीय वाहन उद्योग में सेमीकंडक्टर चिप और दुर्लभ खनिज मैंगनेट की कमी को भी उजागर किया। ये कमियां भारत की चीन पर निर्भरता के कारण आई थीं। लेकिन उन्होंने बताया कि अब भारत में सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन शुरू हो चुका है। साथ ही, देश की स्टार्टअप कंपनियां नई बैटरी तकनीकों जैसे सोडियम आयन, लीथियम आयन, जिंक आयन और एल्युमीनियम आयन बैटरियों पर काम कर रही हैं। गडकरी ने पुराने वाहनों की स्क्रीपिंग को भी दुर्लभ खनिज प्राप्त करने का स्रोत बताया और सरकार की प्रोत्साहन नीतियों का जिक्र किया। गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के बावजूद पेट्रोल और डीजल वाहनों की मांग बढ़ती रहेगी। वाहन विनिर्माण में 15-20 प्रतिशत की वृद्धि जारी है। उन्होंने भारतीय वाहन उद्योग के विकास का जिक्र करते हुए बताया कि जब वे मंत्री बने थे, तब इसका आकार 14 लाख करोड़ रुपये था और अब भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है।



अधिनियम, को लागू करें। सीजन बॉल क्रिकेट को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ के दायरे में लाया जाए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को खेल मंत्रालय के अधीन लाया जाए। याचिका का नेतृत्व कर रही छात्रा ने कहा कि अब समय आ गया है कि बीसीसीआई को खेल मंत्रालय के अधीन लाया जाए। एक बार राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम लागू हो गया तो बोर्ड को राष्ट्रीय खेल बोर्ड के तहत आना ही पड़ेगा।

होने दीजिए। जब वकील ने दलील दी कि रविवार को मैच है और अगर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हुई तो याचिका निर्थक हो जाएगी तो जस्टिस माहेश्वरी ने उन्हें दो टुक़ जवाब दिया- मैच इस रविवार है? हम इसमें क्या कर सकते हैं? रहने दीजिए, मैच होना चाहिए।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह याचिका चार लॉ छात्रों ने दायित्व की है। उनका कहना है कि हाल ही में हुए पहलुगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ मैच

खेलना राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। इससे शहीद हुए जवानों और नागरिकों के बलिदान का अपमान होगा। याचिका के मुताबिक जब हमारे सैनिक अपनी जान दे रहे हैं, उसी देश के साथ क्रिकेट खेलना गलत संदेश देता है और शहीदों के परिवारों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। याचिका में कहा गया है कि मनोरंजन को राष्ट्र की सुरक्षा और गरिमा से ऊपर नहीं रखा जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपील की है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खेल शासन

नेपाल में भ्रष्टाचार व परिवारवाद के खिलाफ़ युवाओं के जबरदस्त आक्रोश को दुनियाँ के हर देश को संज्ञान में लेना ज़रूरी

(लेखक - एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी)

श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन तक जनता का कब्ज़ा, बांग्लादेश में चुनावी धांधली के खिलाफ आंदोलन और म्यांमार में सैन्य तख्तापलट ने दक्षिण एशिया की राजनीति को लगातार अस्थिर बना रखा है। अब नेपाल भी उसी राह पर चलते हुए सत्ता पलट की कगार पर पहुँच गया है। इसका सीधा संकेत है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद से जुड़ रहे समाजों में युवा अब चुप बिल्कुल नहीं बैठेंगे।

नेपाल में पिछले कुछ दिनों में घटित राजनीतिक घटनाक्रम ने पूरे दक्षिण एशिया को हिला दियाहै।भ्रष्टाचार और परिवारवाद से त्रस्त जनता, खासकर युवाओं के जबरदस्त आक्रोश ने मात्र 36 घंटे में सत्ता की गद्दी हिला दी। पाँच पूर्व प्रधानमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने स्थिति को और अधिक उग्र बना दिया। सत्ता पलट की इस तेजी ने यह संकेत दिया है कि नेपाल की जनता अब किसी भी कीमत पर अपारदर्शी शासन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार आम लोग और युवा सड़कों पर उतरे, उसने यह साफ कर दिया कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब वह जनता के विश्वास पर आधारित हो।नेपाल की कुल जनसंख्या का लगभग 20 प्रतिशत यानी 62 लाख लोग युवा हैं, और यही वर्ग देश की राजनीति का भविष्य तय करने वाला है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूँ कि वैश्विक स्तर पर भी यह बात स्पष्ट है कि, किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के हाथों में होता है। नेपाल के युवाओं ने इस बार भ्रष्टाचार और पारिवारिक राजनीति के खिलाफ अपनी ताकत दिखाकर पूरे विश्व को एक सशक्त संदेश दिया है कि अब युवा पीढ़ी नेपो बेबीस यानी नेताओं के बच्चों और वंशवाद की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी। युवाओं की इस ऊर्जा ने नेपाल की राजनीति को हिला कर रख दिया है और यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जनरेशन-जेड (गेन जेड) अब नेपाल का नया इतिहास लिखने जा रही है?

साथियों बात अगर हम नेपाल में हालात इस कदर हद तक बिगड़ बिगड़ने की करें तो, तीनों बड़ी पार्टियों,नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और माओवादी सेंटर,के नेताओं के घरों मेंघुसकर लोगों ने मारपीट की, घरों को आग

के हवाले कर दिया और वित्तमंत्री को सड़कों पर घसीटा गया। एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आगजनी के दौरान उनकी पत्नी की मौत हुई तो उधर जनाक्रोश को और अधिक भड़का दिया। यह दृश्य केवल राजनीतिक विद्रोह का नहीं बल्कि व्यवस्था के खिलाफ पूर्ण असंतोष का प्रतीक है। युवाओं का यह क्रोध इस बात का संकेत है कि अब पारंपरिक राजनीति को बदलने का समय आ चुका है।

साथियों बात अगर हम नेपाल की स्थिति की तुलना श्रीलंका और बांग्लादेश से करने की करें तो,जहाँ हाल के वर्षों में आर्थिक संकट और राजनीतिकअस्थिरता ने जनता को सड़कों पर ला दिया था।

श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन तक जनता का कब्ज़ा, बांग्लादेश में चुनावी धांधली के खिलाफ आंदोलन और म्यांमार में सैन्य तख्तापलट ने दक्षिण एशिया की राजनीति को लगातार अस्थिर बना रखा है। अब नेपाल भी उसी राह पर चलते हुए सत्ता पलट की कगार पर पहुँच गया है। इसका सीधा संकेत है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद से जुड़ रहे समाजों में युवा अब चुप बिल्कुल नहीं बैठेंगे।

साथियों बात अगर हम नेपाल के इस पूरे घटनाक्रम में सोशल मीडिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने की करें तो, नेपाल की लगभग 87 प्रतिशत आबादी मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करती है, जबकि 62 प्रतिशत लोग सक्रिय रूप से फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। ट्विटर और यूट्यूब पर भी युवा लगातार अपने विचार साझा कर रहे हैं। नेताओं के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया पर अपने आलीशान जीवन और लज्जरी छुट्टियों की तस्वीरें पोस्ट करना आग में घी का काम साबित हुआ। जब देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जुड़ा रही हो और नेता तथा उनके परिवार ऐशों-आराम की तस्वीरें साझा करें, तो यह जनता के लिए असहनीय हो जाता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया ने जनाक्रोश को संगठित आंदोलन में बदल दिया।

साथियों बात अगर हम भारत के पड़ोस में यहराजनीतिक उथल- पुथल चिंता का विषय होने की करें तो,नेपाल बांग्लादेश,श्रीलंका म्यांमार और पाकिस्तान सभी वर्तमान में या तो राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहे हैं या सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। म्यांमार में सेना का शासन है, पाकिस्तान में सरकार और सेना के बीच टकराव है, श्रीलंका अब भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और बांग्लादेश में युवाओं के विद्रोह ने लोकतंत्र को झकझोर दिया है।इन सबके बीच नेपाल का यह आंदोलन दक्षिण एशिया में एक नई लहर पैदा कर सकता है।इतिहास की दृष्टि से देखें तो श्रीलंका,पाकिस्तान और म्यांमार कभी अखंड भारत का हिस्सा रहे थे। आज वे दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और सभी देशों में एक जैसी राजनीतिक चुनौतियाँ दिखाई दे रही हैं, भ्रष्टाचार बेरोजगारी, परिवारवाद, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी और युवा असंतोष। यही वजह है कि नेपाल की घटनाएँ केवल एक देश की समस्या नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति के लिए चेतावनी हैं।

साथियों बात अगर हम नेपाल के घटनाक्रम नेपाल में सत्ता पलट का भारत पर सीधा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होने की करें तो,भारत और नेपाल के बीच गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक संबंध हैं। दोनों देशों की खुली सीमा, व्यापार, पानी और ऊर्जा परियोजनाएँ भारत को नेपाल के साथ मजबूती से जोड़ती हैं।यदि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर भारत की सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों की शांति और आर्थिक हितों पर अवश्य पड़ेगा। चीन और पाकिस्तान जैसे देश नेपाल में बढ़ती अस्थिरता का फायदा उठाकर भारत विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसलिए भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह नेपाल की स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समर्थन दे।

साथियों बात अगर हम युवाओं के जागरूकता की करें

तो नेपाल का यह विद्रोह यह भी दर्शाता है कि दक्षिण एशिया के युवाओं में अब जागरूकता का स्तर काफी बढ़ चुका है। वे केवल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। नेपो बेबीस और पारिवारिक राजनीति के खिलाफ उठी यह आवाज़ अब केवल नेपाल तक सीमित नहीं रहेगी,बल्कि बांग्लादेश,श्रीलंका, पाकिस्तान और यहाँ तक कि भारत में भी राजनीतिक परिवारवाद के खिलाफ नई बहस को जन्म देगी।आगे चलकर नेपाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि यह जनआंदोलन केवल सत्ता पलट तक सीमित न रह जाए, बल्कि एक स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था में बदल सके। यदि यह आंदोलन केवल भावनाओं के आधार पर चला और संस्थागत सुधारों तक नहीं पहुँचा, तो नेपाल बार-बार उसी राजनीतिक अस्थिरता का शिकार होगा जो पिछले तीन दशकों से जारी है। लेकिन यदि युवा इस ऊर्जा को सही दिशा देते हैं, तो नेपाल न केवल खुद को बदल सकता है बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए प्रेरणा बन सकता है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि नेपाल में युवाओं का आक्रोश, सत्ता पलट और दक्षिण एशिया की राजनीति-एक अंतरराष्ट्रीय विश्लेषणविषय में युवा पीढ़ी ही अपने देश की राजनीति का भविष्य तय करने वाली है

नेपाल में भ्रष्टाचार व परिवारवाद के खिलाफ़ युवाओं के जबरदस्त आक्रोश को दुनियाँ के हर देश को संज्ञान में लेना ज़रूरी हैं।

(संकलनकर्ता लेखक – कर विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्दमा सीए (एटीसी)

(यह लेखक के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

बेहाल नेपाल

नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाने के बाद उग्र हुआ आंदोलन आखिरकार संवैधानिक संकट में बदल गया और सरकार गिरने का कारण बना। यहां तक कि मंत्रियों के बाद प्रधानमंत्री के.पी. ओली तक को इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। उग्र युवाओं ने संसद, सुप्रीम कोर्ट, मंत्रियों के आवास व कुछ मीडिया हाउस को भी निशाना बनाया। भले ही तात्कालिक रूप से सोशल मीडिया पर बैन को हिसा की वजह बताया जा रहा हो, लेकिन यह प्रतिक्रिया तात्कालिक नहीं थी। युवाओं की दशकों की हताशा और राजनीतिक कदाचार, काहिली व निरंकुशता के चलते गुस्सा नेपाल की सड़कों पर लावा बनकर फूटा है। नेपाल सरकार की सख्ती से आंदोलनकारियों के दमन ने आग में घी का काम किया। नेपाल की राजनीति में अवसरवाद व राजनीतिक अस्थिरता ने भी सरकारों के प्रति युवाओं के आक्रोश को बढ़ाया है। विडंबना देखिए कि 17 बरसों में यहां 14 सरकारें बन चुकी हैं। बहरहाल इस हिंसक प्रतिकार में 19 से अधिक युवाओं को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। दरअसल, शुरुआत में सोशल मीडिया साइटों पर एक विवादास्पद प्रतिबंध ने युवा नेतृत्व वाले जेन-जेड समूह के गुस्से को भड़का दिया। यह समूह सत्ता के शीर्ष पदों पर कथित भ्रष्टाचार और उनकी संतानों के विलासी जीवन के खिलाफ अभियान चला रहा था। इस युवा ब्रिगेड ने लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके दावा किया कि मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की संतानों की फिजूलखर्ची भरी जीवनशैली अवैध धन-दौलत की बढौलत है। इस पोल-खोल अभियान से घबरायी सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का अफसल प्रयास किया। सरकार का यह दांव उस पर ही उलटा पड़ा और सरकार की ही विदाई हो गई। हालांकि, युवाओं का आक्रोश देखते हुए सरकार ने प्रतिबंध हटाने की घोषणा की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैसे इस आंदोलन के दौरान जिस तरह हिंसा, आगजनी व तोड़फोड़ हुई, वह दुर्भाग्यपूर्ण ही कही जाएगी। युवाओं की हिंसक भीड़ ने मंगलवार को संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राजनीतिक दलों के कार्यालयों और मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया। दरअसल, आंदोलनकारी शासन व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते रहे हैं। उनकी मांग रही कि सोमवार को पुलिस गोलाबारी में हुई मौतों के लिये जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दी जाए। अराजकता और अव्यवस्था के बीच, काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर, बालेन शाह, एक प्रभावशाली हितधारक के रूप में उभरे हैं। इस पैंतीस वर्षीय पूर्व रेपर ने भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ आंदोलन का समर्थन करके जेन-जेड का विश्वास जीता है। उन्होंने संसद भंग करने की मांग की है। जिसके बाद सैन्य अधिकारियों और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत हुई। निरस्सेदह, मौजूदा वक्त में सेना की बड़ी भूमिका होने के बाद अब उसके व सुरक्षा एजेंसियों के लिये तात्कालिक चुनौती अस्थिर स्थिति पर नियंत्रण और सामान्य स्थिति को बहाल करने की होगी। आने वाले दिनों में व्यवस्थागत सुधारों के रोडमैप पर चर्चा के साथ बातचीत के जरिये संकट का समाधान करना प्राथमिकता होनी चाहिए। दरअसल, ओली और उनके पूर्ववर्तियों की नीतियों की विफलता ने युवाओं में निराशा व मोहभंग को बढ़ावा दिया है। वहीं इस उथल-पुथल के मूल में नेपाली अर्थव्यवस्था का संकट भी है, जो पर्यटन और प्रवासी नागरिकों द्वारा भेजी जाने वाली रकम पर निर्भर रही है।

विचार मंथन

(लेखक -सनत जैन)

1980 के दशक में जब चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को लिबरलाइजेशन, प्राइवटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ाया। वहीं भारत सामाजिक सुधार और धार्मिक उन्माद की राजनीतिक गुटबाजी में उलझ गया। उस समय भारत और चीन दोनों एक ही आर्थिक व्यवस्था में समान रूप से खड़े थे। चीन ने साहसिक फैसले लेते हुए अपने उद्योगीकरण को कम्युनिस्ट देश होने के बाद भी पूरी गति से आगे बढ़ाया। वहीं भारत मंडल आयोग की सिफारिश पर जाति आधारित आरक्षण तथा कमंडल के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों में व्यस्त था। चीन ने तत्कालीन राष्ट्रपति माओ की नीतियों को खूट्टी में टांगकर आधुनिक

उदारीकरण की राह अपनाई। चीन ने अपनी पुरानी नीतियों को सरल बनाया। प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया। सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त किया। विदेशी कंपनियों के निवेश के लिए नई आकर्षक नीतियां बनाई। उदाहरण स्वरूप, अमेरिका की टेस्ला कंपनी को चीन में कारखाना लगाने में 3 साल का समय लगने का अनुमान था। चीन ने मात्र 18 महीनों में पूरा कारखाना खड़ा करके विश्व को चौंका दिया था। चीन ने अधिकारियों को जवाबदेह बनाया,पर्यावरण नियमों को लचीला बनाकर उत्पादन और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया। चीन की सरकार और वहां के अधिकारियों ने समयबध तरीके से काम करने को अनिवार्य बनाते हुए, जिम्मेदारी सरकार और उसके अधिकारियों ने ली। जिसके कारण चीन में बड़ी तेजी के साथ दुनिया भर के

उद्योगपति और कारोबारी चीन पहुंचने लगे। देखते ही देखते चीन का औद्योगिक विकास और चीनी उत्पाद का कारोबार सारी दुनिया में फैलने लगा। वहीं भारत में लाइसेंस पाने के लिए महीनों नहीं सालो लगते थे। सरकार ने जो नियम कानून बनाए। उसको नेताओं, अधिकारियों ने सत्ता और भ्रष्टाचार के लिए नियम कानून इस तरीके से तैयार किये, कि उसमें भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। हम औद्योगिक विकास और सामाजिक विकास में लगातार पिछड़ते चले गए। आज भारत की संवैधानिक संस्था जिसमें न्यायपालिका हो या विधायिका या कार्यपालिका सभी में लापरवाही व भ्रष्टाचार के कारण आर्थिक और सामाजिक विकास में रोज़ा बने हुए हैं। वैश्विक व्यापार संधि के बाद जब भारत आर्थिक एवं सामाजिक सुधार के दौर पर जब सारी दुनिया में आगे बढ़ सकता

था। उस समय हम पर जाति व्यवस्था धार्मिक धुवीकरण और धार्मिक उन्माद को लेकर आपस में लड़ते रहे। देश को जब आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाना जरूरी था। दुर्भाग्यवश, राजनीति की दलबंदी ने विकास की गति को धीमा कर दिया। सामाजिक विकास की दौड़ में हम पीछे छूटते चले गए। उस समय जो लोग विरोध में थे, वह उदारीकरण का विरोध कर रहे थे। जब वही लोग सत्ता में आए, तो उन्होंने 100 फ़ीसदी एफडीआई के लिए रास्ता खोल दिया। चीन ने पूरी दुनिया के लिए 30 वर्षों में बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। चाहे वह हाई-स्पीड मैग्लेव ट्रेन हो, या हर साल नए पुल व सड़कें बनाने का काम हो। भारत ने औद्योगीकरण की बजाय गरीबी उन्मूलन को केंद्र बिन्दू बनाया।

सही मायने में भारत गरीबी का निवारण नहीं कर पाया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, असल में उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं आया। चीन ने आर्थिक सुधारों से व्यापक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की और हर क्षेत्र में तेजी से विकास किया। आज दुनिया के अधिकांश देशों के घरों में में चाइनीज सामान पहुंच रहा है। बुलेट ट्रेन की बात दूर वहाँ मैग्लेव ट्रेन चल रही है। भारतीय इंजीनियर मेहनती हैं, पर सिस्टम ने उन्हें पीछे धकेल दिया। उन्हें काम करने का मौका ही नहीं दिया।

इसलिए अब समय आ गया है, हम चीन से सबक लें। आसान लाइसेंसिंग नीति अपनाएं, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करें, सामाजिक मुद्दों के साथ-साथ औद्योगिक विकास पर भी ध्यान दें। भारत की विधायिका, कार्यपालिका और

न्यायालय को उनके कार्यों के लिए जिम्मदार ठहराया जाए। जो नियम – कानून बनाते हैं। वह परिणाम मूलक हों। समय पर कार्य करने की बाधता हो। न्यायपालिका भी निश्चित समय – सीमा पर त्वरित निर्णय हों। आम आदमी को स्वतंत्रता से काम करने की छूट हो। सरकारी नियंत्रण खत्म हो। चीन ने जो नीतियाँ बनाई हैं। उससे स्पष्ट है, चीन आर्थिक एवं सामरिक विकास के साथ दुनिया की महाशक्ति बनकर अमेरिका और रूस जैसे देशों के साथ बराबरी पर खड़ा हो गया है। चीन ने अन्य देशों के बाहर जो विस्तार किया है, वह उसकी सफलता का प्रतीक है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। प्राकृतिक संसाधन चीन से ज्यादा भारत के पास हैं। ऐसी स्थिति में विधायिका और कार्यपालिका की जिम्मदारी तय करना होगी।

केरल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति

(लेखक – एल.एस. हरदेनिया)

वैसे तो केरल अनेक चीजों में अन्य राज्यों से आगे है परंतु अभी प्राप्त एक आंकड़े के अनुसार यह बताया गया है कि केरल में 1000 बच्चों की मृत्यु का आंकड़ा 1000 में से 5 है। मतलब यदि केरल में 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से सिर्फ 5 बच्चों की मृत्यु जन्म के समय होती है। यह आंकड़ा अमरीका से भी आगे है।

केरल में जैसा कि बताया गया है कि 1000 शिशुओं में से 5 शिशुओं की मृत्यु होती है जबकि यह आंकड़ा हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर 25 है। मतलब यह कि जब 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से 25 बच्चे पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।

यह आंकड़ा रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर द्वारा किए गए सर्वे पर आधारित है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के अनुसार उन्होंने फिर इस बात को दोहराया है कि यह आंकड़ा अमरीका में बच्चों की मृत्यु दर से भी आगे है। अमरीका में शिशु मृत्यु दर लगभग 5.6 है।

देश के अनेक राज्यों में शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग होता है, परंतु केरल में ऐसी स्थिति नहीं है। केरल में यदि शहरों में 1000 में से 5 शिशु मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो गांवों में भी 1000 में से 5 शिशु मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दोनों का मृत्यु दर का आंकड़ा बराबर है। परंतु

यदि देश में देखा जाए तो 1000 में से 28 बच्चे पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जिनमें शहरों में शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा 19 है। केरल में शहरी और ग्रामीण बच्चों की मृत्यु के आंकड़े में कोई अंतर नहीं है। इसका कारण यह है कि जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं आम लोगों को शहर में प्राप्त होती हैं वही सेवाएं गांवों में भी प्राप्त होती हैं। यदि आज केरल में 1000 में से सिर्फ 5 शिशु मरते हैं तो उसका श्रेय केरल में जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं उसको जाता है।

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 में केरल में यह आंकड़ा 7.42 था। 2012 में यह आंकड़ा 8.2 था और 2023 के आते-आते शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई अंतर नहीं रहा। यह इसलिए कि गांवों में भी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उतनी ही उपलब्ध हैं जितनी शहरों में उपलब्ध हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है।

केरल की स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का अनुभव मुझे भी है। मैं केरल में एक सम्मेलन के संबंध में गया था। रात के 12 बजे मेरे कान में एकाएक दर्द हुआ। मैंने, हमारे जो सम्मेलन के आयोजक थे उनसे कहा कि मुझे कान में बहुत दर्द हो रहा है यदि मेडिकल सहायता मिल जाए तो अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा कि चलिए। मैंने कहा कि अभी तो अस्पताल में ओपीडी (जहां बाहर के लोगों को सुविधाएँ दी जाती हैं) बंद होगी। हमारे मध्यप्रदेश में



अस्पतालों में एक समय सीमा में ओपीडी सेवा प्राप्त होती है। यदि 9 बजे से ओपीडी खुलता है तो 1 बजे बंद हो जाता है। फिर उसके बाद सिर्फ एक इमरजेंसी सेवा प्राप्त होती है। आयोजक ने बताया कि केरल में ऐसा नहीं है। केरल में 24 घंटे एक-सी सुविधा प्राप्त होती है। यदि दिन के 1 बजे रोगी को जो सुविधा प्राप्त होती है वही सुविधा रात के 1 बजे भी प्राप्त होती है। मतलब अस्पताल में सेवाएं 24 घंटे प्राप्त होती हैं। ओपीडी और नॉन-ओपीडी का कोई विभाजन वहां नहीं है। मेडिकल सुविधा शहरों और गांवों में 24 घंटे प्राप्त रहती है। जितनी

शहर में सेवाएं उपलब्ध हैं उतनी ही गांवों में भी उपलब्ध हैं। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति रात के 1 बजे भी अस्पताल पहुंचेगा तो उसे वही सुविधा मिलेगी जो हमारे मध्यप्रदेश में ओपीडी में प्राप्त होती है। यही कारण है कि केरल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई है। केरल में शिशु मृत्यु दर 1000 में से 5 है यह प्रगति अमरीका से भी ज्यादा है और केरल में यह प्रयास है कि यह आंकड़ा और भी कम हो।

(यह लेखक के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

ज्ञेय और ज्ञान का संबंध

दर्शन के क्षेत्र में ज्ञान और ज्ञेय की मीमांसा चिरकाल से होती रही है। आदर्शवादी और विज्ञानवादी दर्शन ज्ञेय की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करते। वे केवल ज्ञान की ही सत्ता को मान्य करते हैं। अनेकात का मूल आधार यह है कि ज्ञान की भांति ज्ञेय की भी स्वतंत्र सत्ता है। द्रव्य के द्वारा जाना जाता है, इसलिए वह ज्ञेय है। ज्ञेय चैतन्य के द्वारा जाना जाता है, इसलिए वह ज्ञान है। ज्ञेय और ज्ञान अन्योन्याश्रित नहीं हैं। ज्ञेय है, इसलिए ज्ञान है और ज्ञान है इसलिए ज्ञेय है, इस प्रकार यदि एक के होने पर दूसरे का होना सिद्ध हो तो ज्ञेय और ज्ञान दोनों की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। द्रव्य का होना ज्ञान पर निर्भर नहीं है और ज्ञान का होना द्रव्य पर

निर्भर नहीं है। इसलिए द्रव्य और ज्ञान दोनों स्वतंत्र हैं। ज्ञान के द्वारा द्रव्य जाना जाता है, इसलिए उनमें ज्ञेय और ज्ञान का संबंध है। ज्ञेय अनंत है और ज्ञान भी अनंत है। अनंत को अनंत के द्वारा जाना जा सकता है। जानने का अगला पर्याय है कहना। अनंत को जाना जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। कहने की शक्ति बहुत सीमित है। जिसका ज्ञान अनावृत होता है, वह भी उतना ही कह सकता है जितना कोई दूसरा कह सकता है। भाषा की क्षमता ही ऐसी है कि उसके द्वारा एक बार में एक साथ एक ही शब्द कहा जा सकता है।

हमारे ज्ञान की क्षमता ही ऐसी है कि हम अनंतधर्मा द्रव्य को नहीं जान सकते। हम अनंत-धर्मात्मक द्रव्य के

एक धर्म को जानते हैं और एक ही धर्म का प्रतिपादन करते हैं। एक धर्म को जानना और एक धर्म को कहना नय है। यह अनेकात और रयाद्वाद का मौलिक स्वरूप है। उनका दूसरा स्वरूप है प्रमाण। अनंत-धर्मात्मक द्रव्य को जानना और उसका प्रतिपादन करना प्रमाण है। हम अनंतधर्मा द्रव्य को किसी एक धर्म के माध्यम से जानते हैं। इसमें मुख्य और गौण दो दृष्टिकोण होते हैं। द्रव्य के अनंत धर्मों में से कोई एक धर्म मुख्य हो जाता है और शेष धर्म गौण। नय हमारी वह ज्ञान-पद्धति है, जिसमें हम केवल धर्म को जानते हैं, धर्मों को नहीं जानते। प्रमाण हमारी वह ज्ञान-पद्धति है, जिससे हम एक धर्म के माध्यम से समग्र धर्मों को जानते हैं।

भारतीय उपमहाद्वीप में डीप स्टेट की सक्रियता और सज्जनशक्ति की जागरूकत

(लेखक -सनत जैन)

1980 के दशक में जब चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को लिबरलाइजेशन, प्राइवटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ाया। वहीं भारत सामाजिक सुधार और धार्मिक उन्माद की राजनीतिक गुटबाजी में उलझ गया। उस समय भारत और चीन दोनों एक ही आर्थिक व्यवस्था में समान रूप से खड़े थे। चीन ने साहसिक फैसले लेते हुए अपने उद्योगीकरण को कम्युनिस्ट देश होने के बाद भी पूरी गति से आगे बढ़ाया। वहीं भारत मंडल आयोग की सिफारिश पर जाति आधारित आरक्षण तथा कमंडल के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों में व्यस्त था। चीन ने तत्कालीन राष्ट्रपति माओ की नीतियों को खूट्टी में टांगकर आधुनिक

उदारीकरण की राह अपनाई। चीन ने अपनी पुरानी नीतियों को सरल बनाया। प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया। सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त किया। विदेशी कंपनियों के निवेश के लिए नई आकर्षक नीतियां बनाई। उदाहरण स्वरूप, अमेरिका की टेस्ला कंपनी को चीन में कारखाना लगाने में 3 साल का समय लगने का अनुमान था। चीन ने मात्र 18 महीनों में पूरा कारखाना खड़ा करके विश्व को चौंका दिया था। चीन ने अधिकारियों को जवाबदेह बनाया,पर्यावरण नियमों को लचीला बनाकर उत्पादन और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया। चीन की सरकार और वहां के अधिकारियों ने समयबध तरीके से काम करने को अनिवार्य बनाते हुए, जिम्मेदारी सरकार और उसके अधिकारियों ने ली। जिसके कारण चीन में बड़ी तेजी के साथ दुनिया भर के

उद्योगपति और कारोबारी चीन पहुंचने लगे। देखते ही देखते चीन का औद्योगिक विकास और चीनी उत्पाद का कारोबार सारी दुनिया में फैलने लगा। वहीं भारत में लाइसेंस पाने के लिए महीनों नहीं सालो लगते थे। सरकार ने जो नियम कानून बनाए। उसको नेताओं, अधिकारियों ने सत्ता और भ्रष्टाचार के लिए नियम कानून इस तरीके से तैयार किये, कि उसमें भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। हम औद्योगिक विकास और सामाजिक विकास में लगातार पिछड़ते चले गए। आज भारत की संवैधानिक संस्था जिसमें न्यायपालिका हो या विधायिका या कार्यपालिका सभी में लापरवाही व भ्रष्टाचार के कारण आर्थिक और सामाजिक विकास में रोज़ा बने हुए हैं। वैश्विक व्यापार संधि के बाद जब भारत आर्थिक एवं सामाजिक सुधार के दौर पर जब सारी दुनिया में आगे बढ़ सकता

था। उस समय हम पर जाति व्यवस्था धार्मिक धुवीकरण और धार्मिक उन्माद को लेकर आपस में लड़ते रहे। देश को जब आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाना जरूरी था। दुर्भाग्यवश, राजनीति की दलबंदी ने विकास की गति को धीमा कर दिया। सामाजिक विकास की दौड़ में हम पीछे छूटते चले गए। उस समय जो लोग विरोध में थे, वह उदारीकरण का विरोध कर रहे थे। जब वही लोग सत्ता में आए, तो उन्होंने 100 फ़ीसदी एफडीआई के लिए रास्ता खोल दिया। चीन ने पूरी दुनिया के लिए 30 वर्षों में बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। चाहे वह हाई-स्पीड मैग्लेव ट्रेन हो, या हर साल नए पुल व सड़कें बनाने का काम हो। भारत ने औद्योगीकरण की बजाय गरीबी उन्मूलन को केंद्र बिन्दू बनाया।

सही मायने में भारत गरीबी का निवारण नहीं कर पाया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, असल में उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं आया। चीन ने आर्थिक सुधारों से व्यापक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की और हर क्षेत्र में तेजी से विकास किया। आज दुनिया के अधिकांश देशों के घरों में में चाइनीज सामान पहुंच रहा है। बुलेट ट्रेन की बात दूर वहाँ मैग्लेव ट्रेन चल रही है। भारतीय इंजीनियर मेहनती हैं, पर सिस्टम ने उन्हें पीछे धकेल दिया। उन्हें काम करने का मौका ही नहीं दिया।

इसलिए अब समय आ गया है, हम चीन से सबक लें। आसान लाइसेंसिंग नीति अपनाएं, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करें, सामाजिक मुद्दों के साथ-साथ औद्योगिक विकास पर भी ध्यान दें। भारत की विधायिका, कार्यपालिका और

न्यायालय को उनके कार्यों के लिए जिम्मदार ठहराया जाए। जो नियम – कानून बनाते हैं। वह परिणाम मूलक हों। समय पर कार्य करने की बाधता हो। न्यायपालिका भी निश्चित समय – सीमा पर त्वरित निर्णय हों। आम आदमी को स्वतंत्रता से काम करने की छूट हो। सरकारी नियंत्रण खत्म हो। चीन ने जो नीतियाँ बनाई हैं। उससे स्पष्ट है, चीन आर्थिक एवं सामरिक विकास के साथ दुनिया की महाशक्ति बनकर अमेरिका और रूस जैसे देशों के साथ बराबरी पर खड़ा हो गया है। चीन ने अन्य देशों के बाहर जो विस्तार किया है, वह उसकी सफलता का प्रतीक है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। प्राकृतिक संसाधन चीन से ज्यादा भारत के पास हैं। ऐसी स्थिति में विधायिका और कार्यपालिका की जिम्मदारी तय करना होगी।

मधुमेह से बचाव में फायदेमंद होती है खड़े रहने की आदत

अक्सर स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए चहलकदमी और व्यायाम का सुझाव दिया जाता है, लेकिन इस मामले में खड़े रहने की आदत भी मददगार साबित हो सकती है। एक हालिया अध्ययन के मुताबिक टाइप 2

फिनलैंड में हुए इस अध्ययन में खड़े रहने की आदत और बेहतर

रोजमर्रा की जिंदगी में खड़े होने का समय बढ़ाने से पुरानी बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है।



खराब इंसुलिन प्रणाली मधुमेह की वजह

एनर्जी मेटाबॉलिज्म और रक्त शर्करा के नियमन में इंसुलिन एक प्रमुख हार्मोन है। कई बार वजन अधिक होने से शरीर में इंसुलिन के सामान्य फंक्शन में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे इंसुलिन संवेदनशीलता कम हो जाती है और टाइप 2 मधुमेह और हृदयरोगों का खतरा बढ़ जाता है। टाइप 2 मधुमेह दुनियाभर में सबसे आम जीवनशैली की बीमारियों में से एक है। इसकी शुरुआत आमतौर पर बिगड़ी हुई इंसुलिन संवेदनशीलता या इंसुलिन प्रतिरोध से होती है। यह एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें शरीर सामान्य रूप से इंसुलिन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है और रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है।

गतिहीन व्यवहार से इंसुलिन प्रणाली प्रभावित

जीवनशैली का इंसुलिन में रुकावट और टाइप 2 मधुमेह के विकास पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। इन समस्याओं की रोकथाम में नियमित शारीरिक गतिविधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि अब तक इंसुलिन की रुकावट पर गतिहीन व्यवहार, लगातार बैठे रहने के बीच ब्रेक और खड़े रहने की आदत के प्रभावों के बारे में बहुत कम जानकारी है। तुर्क पीईटी सेंटर और यूके के संस्थान के हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इंसुलिन में बाधा और गतिहीन व्यवहार के बीच संबंध की जांच की। इससे

निष्क्रियता के साथ टाइप 2 मधुमेह और हृदयरोगों के विकास के बढ़ते जोखिमों को भी देखा। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि रोजमर्रा की नियमित शारीरिक गतिविधि या बैठने के समय, फिटनेस स्तर से अलग स्वतंत्र रूप से खड़े रहना बेहतर इंसुलिन संवेदनशीलता से जुड़ा

एवं तुर्क विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तारु गर्थवेट का कहना है कि अध्ययन के निष्कर्ष रोजाना बैठने के समय के एक हिस्से में लोगों को खड़े रहने के लिए प्रेरित करेंगे। खासकर अगर शारीरिक गतिविधि की जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता है तो यह तरीका मददगार हो सकता है।

जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम होगी

भी जोर देता है। अध्ययन परिणाम बताते हैं कि शारीरिक गतिविधि, फिटनेस या बैठने में लगने वाले समय की तुलना में शरीर में वसा के प्रतिशत में इजाफा इंसुलिन संवेदनशीलता के मामले में अधिक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरी ओर खड़े होना शरीर की संरचना के बावजूद इंसुलिन संवेदनशीलता से जुड़ा था। शोधकर्ताओं का कहना है कि नियमित व्यायाम को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। मगर ऐसा लगता है कि शारीरिक गतिविधि, फिटनेस और गतिहीन व्यवहार भी इंसुलिन मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन परिणाम बताते हैं कि यदि पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं की जा रही तो रोजाना खड़े होने का समय बढ़ाने से जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम में मदद मिल सकती है।

एक हालिया अध्ययन के मुताबिक टाइप 2 मधुमेह से बचाव के मामले में खड़े रहना फायदेमंद होता है। फिनलैंड में हुए इस अध्ययन में खड़े रहने की आदत और बेहतर इंसुलिन संवेदनशीलता के बीच संबंध पाया गया है। इतना ही नहीं रोजमर्रा की जिंदगी में खड़े होने का समय बढ़ाने से पुरानी बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है।



कम सोने की वजह से इन लोगों को जो बीमारियां होती हैं, उसकी जानकारी कम ही लोगों को होती है। दरअसल, कई लोगों को तो यह मानना भी मुश्किल-सा लगता है कि कई वर्षों तक कम सोते रहने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हृदय संबंधी रोग, मधुमेह, स्ट्रोक इत्यादि जैसी अन्य गंभीर बीमारियां घंटों की सही नींद न लेने की वजह से हो सकती हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार 60% से ज्यादा भारतीय सोचते हैं कि नींद लेना कोई प्राथमिकता नहीं है। पिछले कुछ सालों में नींद के महत्व और आवश्यक नींद पूरी न होने से जुड़े खतरों के बारे में बताए जाने के बाद भी लोग नींद को उतनी अहमियत नहीं देते जितना कि व्यायाम को देते हैं। हाल ही में देशभर में हुए सर्वेक्षणों से पता चला है कि देश में नींद की कमी गंभीर चिंता का कारण क्यों है? यहां तक देखा गया है कि लोगों को यह कहने में फख्र महसूस होता है कि वे 4-5 घंटे ही सोते हैं और अपने बाकी के सभी कामों को प्राथमिकता से करते हैं। यदि इस तरह के कम सोने वाले लोग अपनी नौकरी, व्यवसाय व घर-परिवार में कुशल हों तब तो ऐसे लोगों का उदाहरण दूसरे लोगों के लिए पेश किया जाता है कि 'देखो फलाना व्यक्ति ज्यादा सोने में समय बर्बाद नहीं करता है इसलिए तो उसने जीवन में इतना कुछ पा लिया है।' यह बात और है कि आगे जाकर कम सोने की वजह से इन लोगों को जो बीमारियां होती हैं, उसकी जानकारी कम ही लोगों को होती है। दरअसल, कई लोगों को तो यह मानना भी मुश्किल-सा लगता है कि कई वर्षों तक कम सोते रहने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हृदय संबंधी रोग, मधुमेह, स्ट्रोक इत्यादि जैसी अन्य गंभीर बीमारियां घंटों की सही नींद न लेने की वजह से हो सकती हैं। हमारे देश में कई लोग आज भी ऐसे हैं, जो ये मानते हैं कि खराब आना गहरी नींद की निशानी है। उन्हें यह समझाना चुनौतीपूर्ण काम है कि दरअसल खराब आना भी एक गंभीर नींद विकारों के कारणों में से एक है। एक अन्य हाल ही के सर्वेक्षण में यह भी पता चला है कि 19 फीसदी भारतीय वयस्कों की नींद में बाधा का कारण उनके काम करने की शिफ्ट का बदलते रहना है। 132% युवा वयस्क टेक्नोलॉजी के ज्यादा और देर रात तक प्रयोग की वजह से पूरी नींद नहीं ले पाते हैं। एक वयस्क के लिए भी 7 से 9 घंटे की नींद बेहद जरूरी है। कई मामलों में जो लोग इतना सोते हैं उन्हें देखकर अन्य लोग ऐसे लोगों के लिए राय बना लेते हैं कि 'फलाना व्यक्ति आलसी व कमजोर है',

सूखा नारियल सेहत के लिए है कुदरत का वरदान

सूखे नारियल का इस्तेमाल घरों में खीर, आइसक्रीम, स्वीट डिश वगैरह में होता है। ज्यादातर लोग इसे स्वाद बढ़ाने के लिए रेसिपीज में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसकी न्यूट्रीशनल वैल्यू काफी ज्यादा होती है। इस बात पर कम लोगों का ध्यान जाता है। नारियल आपके हार्ट और ब्रेन के लिए अच्छा होता है। साथ ही इसे चबाने से फेशियल एक्सरसाइज भी होती है। इसमें ऐंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ओवरऑल हेल्थ के लिए बढ़िया होते हैं।

ऐंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार

नारियल में फिनॉलिक कंपाउंड होते हैं, जो कि ऐंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये आपकी सेल्स के ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकते हैं। इसमें गैलिक एसिड, कैफिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, पी-कोम्यूरिक एसिड होता है। नारियल आपकी धमनियों में प्लाक बनने से रोकता है जो कि हार्ट ब्लॉकेज की वजह होती है।



कम नींद लेने से हो सकती हैं गंभीर बीमारियां

तो कुछ लोगों को तो खुद ही यह कहने में शर्म महसूस होती है कि 'उन्हें इतना सोने की जरूरत है।' सिर्फ 1 दिन यदि आप 4-5 घंटे से कम सोते हैं, तब आपके शरीर की वे प्राकृतिक कोशिकाएं, जो कैंसर की कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें खत्म करने में सक्षम होती हैं, 70% तक कम हो जाती हैं। आपको कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाएं आपके शरीर में प्रतिदिन बनती हैं। रिपोर्ट के अनुसार नींद की कमी से आंत, प्रोस्टेट और स्तन कैंसर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। कोशिका यह होनी चाहिए कि आप प्रतिदिन नियमित समय पर सोएं और नियमित समय पर उठें।

क्यों नहीं आती है आपको मीठी नींद

- दिनभर की मेहनत और थकान के बाद एक सुखानी नींद पर आपका पूरा हक है लेकिन कई लोगों को बेवजह नींद न आने की शिकायत होती है। आइए मीठी नींद के लिए क्या करें जतन.
- रोज सुबह उठकर कसरत करनी चाहिए।
- अच्छी नींद लेने के लिए कभी भी दिन में न सोएं और सोने से कुछ देर पहले एल्कोहल या कैफीन का सेवन भूलकर भी न करें।
- धूम्रपान न करने से भी नींद अच्छी आती है क्योंकि सिगरेट में पाए जाने वाला निकोटिन नींद में बाधा उत्पन्न करता है।
- कई प्रकार के ड्रग्स भी आराम की नींद लेने में बाधक सिद्ध होते हैं।
- अगर आप शाम को कसरत करेंगे तो आपको सोने में परेशानी हो सकती है।
- जिन महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी होती है उन्हें अक्सर नींद कम आती है। इसलिए शरीर में आयरन की कमी का विशेष ख्याल रखें।
- सुबह जब आप उठें तो सूर्य की तेज रोशनी को कमरे में अंदर आने दें। क्योंकि सही प्रकाश की वजह से शरीर को सही ऊर्जा मिलती है।
- एक बात और ध्यान रखें कि रात को सोते वक्त बेडरूम में रोशनी कम ही रहनी चाहिए, जिससे अच्छी और भरपूर नींद आ सके।
- ... तो जनाब अच्छी व गहरी नींद लीजिए और फिर जिंदगी को पूरी ऊर्जा के साथ जी लेने के लिए खुद को तैयार पाइए।



सेहत का रखना है ख्याल तो अर्जुन फल का करें इस्तेमाल

ऐसे कई लोग होते हैं जो सांसों की बदबू के कारण परेशान रहते हैं और ऐसे में उन्हें किसी से बात करने में भी शर्मिन्दगी महसूस करते हैं। अगर आपका नाम भी ऐसे ही लोगों की लिस्ट में शामिल है तो आप अर्जुन के फल का सेवन करें।

अर्जुन के वृक्ष को भारत में व्यापक रूप से उगाया जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए बेहद ही गुणकारी माना गया है। दरअसल, इसमें ऐंटीऑक्सीडेंट, ऐंटी-इंफ्लेमेटरी और ऐंटीमाइक्रोबियल जैसे विभिन्न औषधीय गुण होते हैं। अर्जुन हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। यह हृदय की मांसपेशियों को मजबूत और टोन करता है और हृदय के समुचित कार्य में मदद करता है। इतना ही नहीं, यह उच्च रक्तचाप से लेकर दर्द, अस्थमा और खांसी आदि कई तरह की समस्याओं को दूर करने में सहायक है। अर्जुन के फल से मिलने वाले कुछ बेमिसाल फायदे -

सांसों की दुर्गंध से मिलता है छुटकारा

ऐसे कई लोग होते हैं जो सांसों की बदबू के कारण परेशान रहते हैं और ऐसे में उन्हें किसी से बात करने में भी शर्मिन्दगी महसूस करते हैं। अगर आपका नाम भी ऐसे ही लोगों की लिस्ट में

शामिल है तो आप अर्जुन के फल का सेवन करें। इस फल में ऐसे होते हैं जो आपके मसूड़ों की समस्याओं और दांतों से खुन बहने में भी मदद कर सकते हैं और आपको ताजा सांस प्रदान करते हैं।

हड्डियों का रखते हैं ख्याल

अगर आप किसी किसी भी प्रकार की हड्डी की समस्या से पीड़ित हैं, तो आपको अपने आहार में अर्जुन फल को अवश्य शामिल करना चाहिए। आप इसका जूस बनाकर पी सकते हैं या इसे कच्चा खा सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया जैसी हड्डियों की परेशानी में भी मदद कर सकता है।

ओरल हेल्थ की समस्याओं को करें दूर

अर्जुन फल खाने से वास्तव में आपकी मसूड़ों की समस्याओं को कम करने और दांतों के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिल सकती है। यह दांतों से खुन बहने से लेकर दांत दर्द, मसूड़ों में दर्द या मसूड़ों से खुन बहना आदि समस्याओं के उपचार में प्रभावी है। आप इस फल को जूस या कच्चा खा सकते हैं। इसके अलावा, अर्जुन के फल के पाउडर का सेवन भी कर सकते हैं और इसे पेस्ट के रूप में उस जगह पर लगा सकते हैं जहां आपको मसूड़े या दांतों की समस्या हो रही है। हालांकि, यह उपाय अपनाने से पहले एक बार डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें।

सैंधा नमक को करें डाइट में शामिल, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

सैंधा नमक कब्ज, हार्ट बर्न, सूजन, पेट दर्द आदि जैसी पाचन समस्याओं के लिए एक उत्कृष्ट घरेलू उपाय है। सैंधा नमक खनिजों और विटामिनों से भरपूर होता है, जो पाचन में सुधार करता है, मल त्याग को बढ़ावा देता है, और आंत से विषाक्त उत्पादों को साफ करने में मदद करता है।

नमक एक ऐसा इंग्रीडिएंट है, जिसका इस्तेमाल हम सभी नियमित रूप से करते हैं। यह भोजन में एक स्वाद शामिल करता है। नमक के बिना भोजन पकाने या उसे खाने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। हालांकि घरों में लोग टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप नमक को अपने स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बनाना चाहते हैं तो आज ही सैंधा नमक खाना शुरू कर दें। सैंधा नमक में सोडियम, पोटेशियम, आयरन,

कैल्शियम, जिंक आदि तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत को लाभ पहुंचाते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में सैंधा नमक का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह स्वस्थ त्वचा और बालों से लेकर वजन घटाने तक कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। सैंधा नमक से मिलने वाले कुछ बेमिसाल फायदे -

पाचन तंत्र के लिए लाभदायक

सैंधा नमक कब्ज, हार्ट बर्न, सूजन, पेट दर्द आदि जैसी पाचन समस्याओं के लिए एक उत्कृष्ट घरेलू उपाय है। सैंधा नमक खनिजों और विटामिनों से भरपूर होता है, जो पाचन में सुधार करता है, मल त्याग को बढ़ावा देता है, और आंत से विषाक्त उत्पादों को साफ करने में मदद करता है। यह भूख की कमी की समस्या को सुधारने में भी मदद करता है।

प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है

सैंधा नमक विटामिन के से भरपूर होता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और आपकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। यह शरीर की हड्डियों के संतुलित रखता है।



एयर इंडिया के 200 विमान यात्री 2 घंटे तक बगैर एसी के तड़पते रहे, अखबार से करते रहे हवा

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली से सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान एआई 2380 में बैठे करीब दो सौ यात्रियों के दो घंटे भारी पड़ गए। विमान में न एसी चल रहा था और न ही बिजली थी। यात्री केवल अखबार से हवा करते रहे और बेचैन होते रहे। जब बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर में तकनीकी खराबी के चलते 200 से ज्यादा यात्रियों को करीब दो घंटे तक विमान में घंटे रहने के बाद उतार दिया गया। रात 11 बजे उड़ान भरने वाली इस फ्लाइट में न तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम काम कर रहा था और न ही बिजली की सप्लाई ठीक थी। हेरानी की बात ये रही कि क्रू मेंबर्स ने यात्रियों को इस अवानक लिए एफ फैसले की कोई वजह नहीं बताई। एयर इंडिया की ओर से भी इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यात्रियों में नाराजगी साफ देखी गई, क्योंकि इतनी बड़ी असुविधा के बाद भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। विमान में बैठे यात्रियों को गर्मी से हाल बेहाल हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में यात्री अखबार और मेगजिन को पंखे की तरह इस्तेमाल करते नजर आए। एक यात्री, जो पीटीआई के प्रकाश भी थे, ने बताया कि दो घंटे तक विमान में बिना किसी ठोस जानकारी के इंतजार करवाया गया। आखिरकार, सभी यात्रियों को विमान से उतारकर टर्मिनल भेज दिया गया। यह घटना एक बार फिर विमानन सेवाओं में तकनीकी खामियों और यात्रियों की सुविधा को लेकर सवाल खड़े करती है। सोशल मीडिया पर यात्रियों ने अपनी भड़ास निकाली और एयर इंडिया से जवाब मांगा। अब देखा ये है कि एयर इंडिया इस मामले पर क्या रुख अपनाती है और यात्रियों को इस असुविधा का कोई मुआवजा मिलेगा या नहीं।

कैलाश मानसरोवर से दर्शन कर लौट रहे अयोध्या के 8 श्रद्धालु नेपाल में फंसे

अयोध्या (एजेंसी)। कैलाश मानसरोवर से दर्शन कर लौटते समय नेपाल-चीन सीमा पर स्थित हिल्सा बॉर्डर (नेपाल) में अयोध्या के आठ श्रद्धालु फंसे हुए हैं। नेपाल में जारी तनाव के कारण वे भारत लौटने में असमर्थ हैं इस स्थिति को देखकर गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। विधायक सिंह ने अपने पत्र में भारत सरकार से अपील की है कि नेपाल में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित रूप से भारत लाने के लिए जरूर कदम उठाए। उन्होंने संबंधित मंत्रालयों और अधिकारियों को निर्देशित करने की भी मांग की है। वहीं, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने भी मुद्दे को गंभीरता से लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। सांसद प्रसाद ने भरोसा दिलाया कि वे खुद गृह मंत्रालय से बावचीत कर श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी के प्रयास करूंगा। गोसाईगंज निवासी कुछ लोग नेपाल बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। इन सभी का परिवार बेहद चिंतित है। उन्होंने कहा हमारी एक ही आस है कि सरकार जल्द से जल्द उन्हें भारत वापस लाए। कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटते समय अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर खराब मौसम और परिवहन संबंधी समस्याएं यात्रियों के फंसे रहने का प्रमुख कारण बन रही हैं।

झारखंड में जर्जर मकान गिरने से दो बच्चों समेत तीन की मौत

रांची (एजेंसी)। झारखंड के धनबाद जिले में बुधवार शाम भारी बारिश के बाद एक जर्जर मकान गिर गया जिसमें दबने से दो बच्चों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। घटना लोदना पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले बीसीसीएन के एक फ्लॉटर में हुई। मकान ढहने के बाद कम से कम सात लोग मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों और एक खुदाई मशीन की मदद से सभी को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि सात लोगों को अस्पताल लाया गया था। उनमें से तीन को मृत घोषित कर दिया गया और चार अन्य का इलाज जारी है।

पटना में राजद कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या

पटना (एजेंसी)। बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के एक कार्यकर्ता, राज कुमार राय उर्फ अला राय, की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास गली नंबर 17 में रात करीब 10 बजे हुई। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद घायल अला राय को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से छह खाली कारतूस बरामद किए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वारदात में दो से ज्यादा लोग शामिल थे। इस हत्या के पीछे का सही कारण अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अला राय राजनीति में सक्रिय थे और जमीन से जुड़े कारोबार में भी शामिल थे। पुलिस सभी संभावित फलतुओं से मामले की जाँच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने में लिए सीसीटीवी फुटेज खगाल रही है। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने घटना को रोकाने वाला बताकर बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधा। फिलहाल, पुलिस मुक्तक के ड्राइवर से भी पूछताछ कर रही है ताकि कोई सुरांग मिल सके।

सीमा पार कर भारत आई बांग्लादेशी युवती और उसके पति गिरफ्तार

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान के धौलपुर में एक बांग्लादेशी युवती और उसके भारतीय पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवती, जिसका नाम जन्नत खानम उर्फ ख़ेहा जारविन है, अपने फेसबुक प्रेमी कबीर खान से मिलने के बाद अवैध रूप से भारत में रह रही थीं। जन्नत खानम, जो बांग्लादेश निवासी है, कि साल 2023 में फेसबुक के माध्यम से धौलपुर के कबीर खान से दोस्ती हुई थी। यह दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। दिसंबर 2024 में, जन्नत एक अन्य महिला, तानिया, के साथ अवैध रूप से सीमा पार कर भारत आई। तानिया जन्नत को कोलकाता के आईटी उद्यम जेन्नत का आधार का बनावया। इसके बाद, जन्नत मुंबई और फ़ि इंदौर गई, जहाँ से कबीर जन्नत को अपने साथ ले आया।

टीएमसी का दावा- उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा ने 20 करोड़ में खरीदा एक सांसद

कोलकाता (एजेंसी)। उपराष्ट्रपति के पद पर चुने गए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने अभी अपने पद की शपथ भी नहीं ली कि विपक्षी दल टीएमसी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव ने दावा किया कि भाजपा ने वोट खरीदने के लिए प्रति सांसद 15 से 20 करोड़ रुपये खर्च किए। लोकसभा में टीएमसी संसदीय दल का नेतृत्व करने वाले अभिषेक ने भाजपा पर लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए धनबल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेता मंगलवार को हुए चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए पैसों की बोरियां लेकर आए थे।

दिल्ली से लौटने के बाद कोलकाता हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में अभिषेक ने कहा, कुछ लोगों से बात करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि भाजपा ने वोट खरीदने के लिए

प्रत्येक व्यक्ति पर 15-20 करोड़ रुपये खर्च किए। जनप्रतिनिधि के रूप में चुने गए सदस्य लोगों के विश्वास और भावनाओं को बेच रहे हैं। प्रतिनिधियों को खरीदा जा सकता है, लेकिन लोगों को नहीं। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के सभी 41 सांसदों (28 लोकसभा सदस्य और 13 राज्यसभा सदस्य) ने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में मतदान किया। अभिषेक ने कहा, सुदीप बंडोपाध्याय और सौगत रॉय अस्वस्थ होने के बावजूद आए तथा मतदान किया। उन्होंने सवाल किया कि राजग के आंकड़े अनुमान से अधिक कैसे हो गए, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया के आंकड़े कम रह गए, जबकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पहले दावा किया था कि 315 सांसदों ने रेड्डी को समर्थन देने का वादा किया था।

अभिषेक ने कहा, 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा ने राज्य में बड़े पैमाने पर नकदी लाने की कोशिश की और

असफल रहे। 2024 में उन्होंने मतदान कर्मियों को खरीदने की कोशिश की, कुछ को 5,000 रुपये और अन्य को 10,000 रुपये का भुगतान किया। लेकिन बंगाल के लोगों ने उन्हें दिखा दिया कि नेताओं को खरीदा जा सकता है, लोगों को नहीं। यही कहानी उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड में भी दोहराई, जहां विधायकों की खरीद-फरोख्त के बाद सरकारें गिर गईं। अभिषेक ने विपक्षी खेमे में विश्वासघात की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया, चूँकि, गुप्त मतदान था, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि क्या क्रॉस वोटिंग हुई या विपक्षी सदस्यों के वोट खारिज कर दिए गए। अगर मैं 'क्रॉस वोटिंग' को स्वीकार भी कर लूं, तो आम आदमी पार्टी (आप) जैसी कुछ पार्टियां हैं, जिसकी एक महिला सांसद खुलेआम भाजपा का समर्थन करती है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलती हैं। ऐसे दो-चार सांसद हैं। उन्होंने पिछले कुछ मामलों से तुलना करते हुए भाजपा पर बार-बार धन का



दुरुपयोग कर पलड़ा अपने पक्ष में झुकाने का आरोप लगाया। भाजपा ने तृणमूल नेता के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे विपक्षी एकता की कमी को दर्शाते हैं। भट्टाचार्य ने कहा, मैं उनकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देकर उन्हें तबज्जों नहीं देना चाहता। लेकिन इस उपराष्ट्रपति चुनाव ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि राजग एकजुट है, जबकि विपक्ष बंटा हुआ है।

बिहार, जम्मू-कश्मीर में उप चुनाव और राज्यसभा की रिक्त 4 सीटों पर एक साथ होगा चुनाव !

नई दिल्ली (एजेंसी)। बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा पूरे देश में है।अगले महीने के अंत तक ऐलान की संभावना है। यही नहीं चुनाव आयोग से सूत्रों का कहना है कि इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर की दो विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी घोषित किए जा सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में बीते साल ही चुनाव हुए थे, लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला दो सीटों से मैदान में उतरे थे। वह दोनों सीटों से जीत गए थे और गान्दरबल से ही विधायक बने रहने का फैसला लिया, जबकि बडगाम सीट छोड़ दी थी। तब से ही गान्दरबल की सीट खाली है। इसके अलावा नगरोटा विधानसभा के विधायक देवेन्द्र सिंह राणा का निधन हो गया था, जिसके चलते यह सीट भी खाली है।ऐसे में करीब एक साल बाद इन दोनों सीटों पर आयोग चुनाव करने की तैयारी में है।



तैयारी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर पहलगाम आतंकों हमले के चलते ये टलते रहे और अब बिहार इलेक्शन के साथ ही यहां भी वोटिंग कराने का प्लान है।इसके अलावा जल्दी ही राज्यसभा की 4 सीटों पर भी चुनाव कराए जा सकते हैं। ये चुनाव भी लंबे समय से अटकते हुए हैं। इन सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 सांसदों का कार्यकाल फरवरी 2021 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन अब तक चुनाव का इंतजार है। इन सांसदों में कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे। फिलहाल वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और कांग्रेस से भी उन्होंने दूरी बना ली है। ऐसे में देखना होगा कि राज्यसभा सीटों के चुनाव में किसकी ओर से किसे उतारा जाता है।

राहुल और तेजस्वी चाहे जितना भी गाली दें, बिहार की जनता गुमराह नहीं होगी: गोयल

पटना (एजेंसी)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पूरी तरह से विफल हो चुके हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी या राजद नेता तेजस्वी चाहे जितना भी बोलें या गाली दें, बिहार की जनता गुमराह नहीं होगी। पटना में गोयल ने कहा कि विपक्ष हमें हराने का बहाना ढूँढ रहा है। मैं राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी की मां को गाली देने की कड़ई निंदा करता हूँ।

यह विवाद एक वायरल वीडियो के बाद शुरू हुआ, जिसमें राहुल गांधी की यात्रा में एक व्यक्ति ने पीएम की मां को गाली दी थी। दरभंगा पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। गोयल ने आगे कहा कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार पूरे विश्वास के साथ बिहार की सेवा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि एनडीए बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

गोयल ने नए जीएसटी एक्टों की भी समर्थन करते हुए कहा कि जैसे-जैसे चीजें सस्ती होंगी, मांग बढ़ेगी और इससे व्यापार जगत को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ा बदलाव करके



रोजमर्रा की वस्तु को सस्ता करने का काम किया है। दूध, पेट्रोल, तेल, कपड़े, घड़ियां, जूते और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए स्टेशनरी, सब सस्ते हो गए हैं...कई चीजें 0 फीसदी जीएसटी पर उपलब्ध हैं।

उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बीमा सुविधाओं में जीएसटी स्लैब हैं। उन्होंने कहा

आज घरे में रेंफ्रिजरेटर, टीवी और एसी जैसी सभी चीजें सस्ती करके इन लोगों के जीवन में एक नया उत्साह, अच्छी चीजों के लिए उत्साह लाया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब के कारण लोगों के पास रोजगार के अधिक अवसर होंगे, क्योंकि सस्ते उत्पादों की उपलब्धता से उनकी मांग बढ़ेगी, जिससे उद्योग का विस्तार होगा।

मोदी सरकार के मंत्रियों के पास क्रिप्टो करेंसी, किसी के पास दशकों पुराने दोपहिया वाहन और रिवाॅल्वर

नई दिल्ली (एजेंसी)। मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने वर्ष 2024-25 की अपनी संपत्तियों की जानकारी साझा की है। इसमें किसी के पास क्रिप्टोकॉरेसी, किसी के पास दशकों पुराने दोपहिया वाहन हैं। जयंत चौधरी एकमात्र मंत्री हैं, जो बिहार के क्रिप्टोकॉरेसी अभी भी नियामकीय अनिश्चितताओं से जूझ रही हैं। आरबीआई ने निवेशकों को वरचुअल करेंसी के जोखिमों के बारे में बार-बार चेतावनी दी है। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने अपनी

संपत्ति में 37 साल पुराना स्कूटर और एक रिवाॅल्वर शामिल होने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक दोपहिया वाहन के अलावा 27 लाख रुपये से अधिक के आभूषण और 19 लाख से अधिक के म्यूचुअल फंड निवेश की भी घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 1.2 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 1,679 ग्राम सोने के आभूषण, 10 किलोग्राम चांदी के आभूषण और हरे के आभूषण सहित अन्य संपत्ति घोषित की है।

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने 74 लाख रुपये से अधिक

मूल्य के स्वर्ण आभूषण और एक स्कूटी सहित अन्य संपत्ति घोषित की है। रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिंदू ने अपनी संपत्ति में 1997 माडल की मारुति एस्टीम कार और एक पिस्तौल शामिल होने की जानकारी दी है। रिवहन मंत्री नितिन गडकरी की संपत्ति में 31 साल पुरानी एक एम्बेसडर कार के अलावा दो अन्य कारें शामिल हैं। उन्होंने 37 लाख रुपये से ज्यादा मूल्य के सोने के आभूषण भी घोषित किए हैं, जबकि उनकी पत्नी कंचन नितिन अधिकारी ने 28 लाख रुपये से ज्यादा मूल्य के सोने के आभूषण घोषित किए हैं। अन्नपूर्णा देवी



और सावित्री ठाकुर के पास असलहें मोदी सरकार की दो महिला मंत्रियों के पास असलहें भी हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अन्य संपत्तियों के अलावा एक रिवाॅल्वर, एक राइफल, एक ट्रैक्टर और लगभग एक

करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश की जानकारी दी है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने 67 लाख रुपये से अधिक मूल्य के स्वर्ण आभूषणों के अलावा एक डबल बैरल बंदूक और एक रिवाॅल्वर घोषित की है।

राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सीआरपीएफ ने उठाया सवाल... वे सुरक्षा को गंभीरता से नहीं ले रहे

-पत्र की एक प्रति कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजी गई

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के अनशेड्यूल्ड विदेश दौरे पर आपत्ति जाहिर की है। सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने के मामले में उन्हें पत्र लिखा गया है। यह पत्र सीआरपीएफ के वीवीआईपी सुरक्षा प्रमुख ने जारी किया है। इस पत्र को एक प्रति कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भेजी गई है। पत्र 10 सितंबर को जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी लगातार उन सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो उनकी सुरक्षा टीम ने निर्धारित किए हैं। वीवीआईपी सुरक्षा प्रमुख ने राहुल गांधी के सुरक्षा के प्रति रखेये पर भी सवाल उठाकर कहा कि वह इस सुरक्षा का गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें एएसएल (सुरक्षा घेरा एडवांस सिनियोरिटी लाइजन्) कवर शामिल है। यह देश की सबसे ऊंची सुरक्षा श्रेणियों में से एक है, जिसमें बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान हर वक्त सुरक्षा में तैनात रहते हैं। बता दें कि बिहार में 'वोट अधिकार यात्रा' संपन्न करने के बाद राहुल गांधी अचानक विदेश यात्रा पर चले गए। ट्विटर पर उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही थीं। हालांकि वह उपराष्ट्रपति चुनाव में शामिल होने के लिए भारत वापस आ गए और पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं।

भारत-नेपाल सीमा पर घुसपैठ रोकने एसएसबी के 60 हजार जवान तैनात; जेल तोड़कर भागे 60 कैदी पकड़े

नई दिल्ली (एजेंसी)। नेपाल में भड़की हिंसा और अराजकता का असर अब भारत-नेपाल सीमा पर साफ देखने को मिल रहा है। घुसपैठियों से सीमा की सुरक्षा को लेकर भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 50 बटालियन यानी करीब 60 हजार जवानों को उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम से लगती सीमा पर मुस्तैद कर दिया है। इनका मकसद किसी भी अग्रिम घटना को रोकना और नेपाल से जेल तोड़कर भागे कैदियों की घुसपैठ को रोकना



ऐसे 60 कैदियों को गिरफ्तार किया है। इन्हें कुछ भारतीय कैदी भी शामिल हैं। एसएसबी अधिकारियों के मुताबिक पकड़े गए कैदियों को स्थानीय पुलिस को सौंपा गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। सूत्रों का कहना है कि नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों ने भारत को अलर्ट किया है कि जेल से भागे अपराधियों में से कई

भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। नेपाल ने यह भी अनुरोध किया है कि यदि ऐसे किसी कैदी को पकड़ा जाए तो उसे वापस नेपाल की जेलों में भेजने की प्रक्रिया अपनाई जाए।

इसी बीच, नेपाल से बड़ी संख्या में लोग भारत का रुख कर रहे हैं। अब तक करीब 500

लोग, जिनमें ज्यादातर भारतीय हैं, नेपाल से भारत आ चुके हैं। दस्तावेजों की जांच के बाद ही उन्हें सीमा पार करने दिया जा रहा है। वहीं, नेपाली नागरिकों का कहना है कि वे फिलहाल अपने देश की हिंसा और अस्थिरता के कारण वापस नहीं जाना चाहते। हालांकि, एसएसबी ने साफ किया है कि भारत-नेपाल सीमा को बंद नहीं किया गया है। पैदल और वैध मार्गों से लोगों को दस्तावेज जांचकर प्रवेश दिया जा रहा है। हां, ट्कां और वाणिज्यिक परिवहन पर रोक लगी हुई है। सीमा पर गश्त और प्लेग मार्च तेज कर दिया गया है। एसएसबी और नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स (एपीएफ) के बीच समन्वय पहले की तरह ही जारी है। नेपाल की आंतरिक अस्थिरता ने न केवल पड़ोसी देश की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है, बल्कि भारत की सीमाई सुरक्षा के लिए भी नए खतरे पैदा कर दिए हैं।

भारत सरकार की सलाह : रूसी सेना में भर्ती के झांसे में ना आएँ युवा

नई दिल्ली (एजेंसी)। रूसी सेना में भर्ती कर भारतीयों को यूक्रेन से जंग में इस्तेमाल करने की खबरें आ रही थीं। अब इसी को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे ऑफरों से दूरी बनाए। इसके अलावा रूस से अपील की है कि वह उन भारतीयों को वापस भेजे, जो किसी भी तरह से झांसे में आकर उसकी सेना में शामिल हो गए हैं। सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वे रूसी सेना में शामिल होने के किसी झांसे में ना आए। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि ऐसे किसी भी ऑफर को स्वीकार न करें क्योंकि यह खतरा से भरा रास्ता है। उल्लेखनीय है कि पिछले तीन वर्ष से भी अधिक समय से यूक्रेन के साथ जंग में उत्तरी रूस की सेना में समय-समय पर भारतीय नागरिकों की भर्ती की जाती रही है। रूस की सेना में भर्ती होने वाले भारतीयों के परिवारों का कहना है कि सेना में भर्ती के बाद उन्हें वापस नहीं आने दिया जाता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती से संबंधित मीडिया के सवालों के जवाब में गुरुवार को कहा कि भारतीय नागरिकों को इस तरह के प्रस्ताव से दूर रहना चाहिए क्योंकि इसमें खतरा है। उन्होंने कहा, हमने हाल ही में रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती की खबरें देखी हैं। सरकार ने पिछले एक साल में कई मौकों पर इस तरह की कार्रवाई में निहित जोखिमों और खतरों के बारे में बताया है और लोगों को आगाह किया है कि वे इससे दूर रहें। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली और मॉस्को दोनों में रूसी अधिकारियों के साथ भी मामला उठाया है। हमने रूस से अनुरोध किया है कि इस प्रैक्टिस को समाप्त किया जाए और हमारे नागरिकों को वापस किया जाए। हम प्रभावित भारतीय नागरिकों के परिवारों के साथ भी संपर्क में हैं। हम एक बार फिर सभी भारतीय नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे रूसी सेना में शामिल होने के किसी भी ऑफर से दूर रहें क्योंकि यह खतरा से भरा रास्ता है। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर सभी भारतीय नागरिकों से रूसी सेना में शामिल होने के किसी भी प्रस्ताव से दूर रहने का आग्रह करते हैं क्योंकि यह खतरा से भरा है।

बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को मौत की सजा दिए जाने पर बोला सुप्रीम कोर्ट...

मौत की सजा सुनाने से पहले अदालतें बहुत सावधानी बरतें

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2014 में उत्तराखंड में 7 साल की बच्ची के दुष्कर्म और हत्या मामले में मौत की सजा पाए दोषी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा सुनाने से पहले अदालतों को बहुत सावधानी बतानी चाहिए। इस मामले को लिटिल निर्भया कहा गया था और इससे पूरे उत्तराखंड में गुस्सा था। जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने ट्रायल कोर्ट और उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसे व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे मौत की सजा सुनाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच में कई कमियां थीं और अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा। यह मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी-अपीलकर्ताओं के अपराध को साबित करने के लिए परिस्थितियों की पूरी और अटूट श्रृंखला स्थापित करने में



विफल रहा है। जस्टिस मेहता ने फैसला सुनाते हुए अदालतों से मौत की सजा सुनाते समय सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि कैपिटल पनिशमेंट की प्रकृति ऐसी है कि इसे केवल रेपेस्ट और फिर् उसकी हत्या कर दी। ट्रायल कोर्ट ने 2016 में आरोपी को दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने भी 2018 में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

था कि बच्ची 29 अप्रैल, 2014 को लापता हो गई थी। उसका शव अगले दिन मिला था। पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर् उसकी हत्या कर दी। ट्रायल कोर्ट ने 2016 में आरोपी को दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने भी 2018 में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

संक्षिप्त समाचार

पूर्वी कांगो में इस्लामिक स्टेट से जुड़े विद्रोहियों ने 60 लोगों का कत्ल किया

लुबेरो , एजेंसी। पूर्वी कांगो में मंगलवार रात को इस्लामिक स्टेट से जुड़े विद्रोही समूह एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स (एडस) ने हमला किया, जिसमें कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई। यह हमला उस समय हुआ जब लोग एक अंतिम संस्कार में इकट्ठा हुए थे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने मीडिया को बताया, लगभग 10 हमलावर थे। उनके पास माघेट (बड़ा चाकू) थे। उन्होंने लोगों को एक जगह इकट्ठा होने को कहा और फिर उन्हें मारना शुरू कर दिया। मैंने लोगों को चीखते सुना और बेहोश हो गई। लुबेरो क्षेत्र के प्रशासक कर्नल एलन किवेवा ने बताया कि मरने वालों की संख्या 60 के आसपास है, लेकिन अंतिम आंकड़ा अभी साफ नहीं है। उन्होंने कहा, हमने क्षेत्र में सेवाएं भेजी हैं ताकि लोगों की गिनती की जा सके। मंगलवार को ही बेनी क्षेत्र में एडीएफ ने एक और हमला किया था, जिसमें 18 लोग मारे गए थे। कांगो-युगांडा सीमा पर सक्रिय एडीएफ ने 2019 में इस्लामिक स्टेट के प्रति निष्ठा जताई थी। कांगो और युगांडा की कार्यवाहियों के बावजूद यह समूह नागरिकों पर हमले कर रहा है। जुलाई में इतुरी प्रंत में एडीएफ ने दो बड़े हमले किए थे, जिनमें 34 और 66 लोग मारे गए थे। क्षेत्र में कई समूह सक्रिय हैं, जिनमें रवांडा समर्थित एम23 विद्रोही और कांगो सरकार के बीच बड़ा संघर्ष शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त वोल्कर तुर्क ने कहा कि सुरक्षा की कमी का फायदा उठाकर एडीएफ हमले कर रहा है। स्थानीय लोग डर और अनिश्चितता में जी रहे हैं, और स्थिति लगातार बिगड़ रही है।

अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा-रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाने को तैयार

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने मंगलवार को यूरोपीय देशों के साथ बातचीत में रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाने को तैयार है। बेसेंट ने कहा कि रूस पर प्रतिबंध तभी सफल होगा, जब यूरोपीय देश अमेरिका का साथ देंगे। बेसेंट ने यूरोपीय देशों के दूत को राष्ट्रपति ट्रम्प की रणनीति के बारे में बताया।

जापान में नए पीएम का चुनाव 4 अक्टूबर को

टोक्यो, एजेंसी। जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) चार अक्टूबर को निवर्तमान प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा की जगह नए नेता का चुनाव करेगी। यह चुनाव एक सरलीकृत मतदान प्रक्रिया के बजाय औपचारिक प्रतियोगिता के बाद होगा। एलडीपी के एक वरिष्ठ सांसद ने कहा कि वित्त विशेषज्ञ व दक्षिणपंथी साने ताकाइची ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दूसरी तरफ, कृषि मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने भी ताल ठोक़ी है। वह पूर्व प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइजुमी के पुत्र हैं। इनके अलावा तीन और प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन औपचारिक रूप से दावेदारी फिलहाल किसी ने भी नहीं पेश की है। प्रतियोगिता के पहले दौर में डाइट में प्रत्येक एलडीपी सांसद एक वोट डालता है और पार्टी के सभी सदस्यों की पसंद को डाइट सदस्यों के वोटों के बराबर अनुपात में विभाजित किया जाता है ताकि परिणाम पार्टी सदस्यों के व्यापक विचारों को प्रतिबिंबित करे। ताकाइची और कोइजुमी सितंबर 2024 में नेतृत्व की दौड़ में भाग ले चुके हैं और कमरा: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे। इसमें इशिबा ने जीत हासिल की थी। सरकार के शीर्ष प्रवक्ता के एक करीबी सूत्र के अनुसार, अन्य संभावित उम्मीदवारों में पूर्व विदेश मंत्री तोशिामित्सु मोटेगी और मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी भी शामिल हैं।

बांग्लादेश ने भारत को 1,200 टन हिल्सा के निर्यात की दी अनुमति

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश ने दुर्गा पूजा से पहले भारत को 1,200 टन हिल्सा मछली के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है। बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार देर रात एक अधिसूचना में कहा, सरकार ने चालू वर्ष में भारत को 1,200 मीट्रिक टन हिल्सा सशर्त निर्यात करने का नीतिगत निर्णय लिया है। इच्छुक निर्यातकों से 11 सितंबर शाम 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सरकार ने प्रति किलोग्राम हिल्सा का न्यूनतम निर्यात मूल्य 12.50 अमेरिकी डॉलर निर्धारित किया है।

भारतवंशी तेजस्वी को टाइम मैगजीन का किड ऑफ द ईयर अवार्ड

टेक्सास, एजेंसी। भारतवंशी तेजस्वी मनोज को टाइम मैगजीन के किड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया गया है। 17 वर्षीय तेजस्वी वुड्स को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने और उसकी रिपोर्ट करने में मदद करने का काम करती हैं। टेक्सास के फ्रिस्को की तेजस्वी को उनके नवाचार शीलड सीनियर्स के लिए प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने कहा, बुजुर्ग अमेरिकियों को सुरक्षा की जरूरत है।

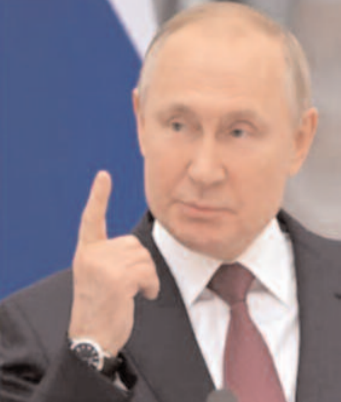
लड़ाई का एक और मोर्चा खुलने का बढ़ा खतरा, पोलैंड का दावा- हवाई क्षेत्र में घुसे रूसी ड्रोन मार गिराए

वारसॉ, एजेंसी। पोलैंड की सेना ने बुधवार को दावा किया कि उन्होंने रूस के ड्रोन्स को मार गिराया है। पोलैंड का कहना है कि रूसी ड्रोन्स ने यूक्रेन पर हमले के दौरान उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। पोलैंड की सेना ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि आज रूस द्वारा जसे यूक्रेन पर हमला किया जा रहा था, तो उस दौरान रूसी ड्रोन्स जैसी चीजों ने बार-बार हमारे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। इन वस्तुओं की पहचान कर उन्हें तबाह कर दिया गया।

पोलैंड की सेना ने जारी किया बयान: बयान में कहा गया है, पोलिश हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सरसन्न बलों के ऑपरेशनल कमांडर ने सभी जरूरी कदम उठाए हैं। पोलैंड के विमान और सहयोगी विमान हमारे हवाई क्षेत्र



में उड़ान भर रहे हैं, और जमीनी वायु रक्षा और रडार टोही प्रणालियां भी अलर्ट पर हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब पोलैंड ने अपने हवाई क्षेत्र में किसी ड्रोन को निशाना बनाया है। यह



घटना ऐसे समय घटी है, जब पोलैंड के राष्ट्रपति ने मंगलवार को ही अपने एक बयान में चेतावनी दी कि रूस, अन्य यूरोपीय देशों पर भी हमला कर सकता है। एहतियातन कई हवाई अड्डे बंद किए गए

भूकंप से उठी चिंगारी कैसे बन गई ज्वाला? नेपाल में जेन जेड के लीडर की अद्भुत कहानी

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल में जेन जेड आज भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, बेरोजगारी और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ सड़कों पर है। इस आंदोलन की जड़ें एक दशक पहले आई उस त्रासदी से जुड़ी हैं, जिसने हिमालयी राष्ट्र को हिलाकर रख दिया था। वह था 2015 का विनाशकारी भूकंप। इस भूकंप ने न केवल घरों और जंदगियों को तोड़ा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को भी गढ़ा, जो आज जेन जेड के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं- सुदन गुरुंग।

भूकंप ने बदली जंदगी : रिपोर्ट के मुताबिक, 38 वर्षीय सुदन गुरुंग कभी थमेल के नाइटलाइफ और पार्टी सर्किट का जाना-माना चेहरा थे। वे थमेल की पार्टी सर्किट में डीजे सेट्स और क्लब आयोजनों से जुड़े थे लेकिन उनका जीवन 2015 के भूकंप के बाद पूरी तरह बदल गया। गुरुंग ने उस समय कहा था, मेरी बाहों में एक बच्चे ने दम तोड़ा। मैं उस पल को कभी नहीं भूल सकता। इसी असह्यता से जन्म हुआ हमी नेपाल का। यह एक स्वयंसेवी संगठन है जो चावल की बोरियों के दान से शुरू हुआ और धीरे-धीरे संगठित रूप लेने लगा। एक दशक बाद, यही संगठन नेपाल के जेन जेड की पहचान बन चुका है।

पार्टी से समाज सेवा तक : भूकंप से पहले गुरुंग का जीवन चावल, डीजे सेट और इवेंट्स के इव-गिद घूमता था। नेपाली रॉक बैंड सिंगार-सिंगारइट और अभया एंड द स्टीम इंजन्स बैंड की प्रंटवुमन अभया



सुब्बा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, नाइटलाइफ में उनकी पृष्ठभूमि ने उन्हें लोगों की नब्ब पढ़ने की कला सिखाई थी। अब वे इस कौशल का उपयोग युवा स्वयंसेवकों को एकजुट करने में करते हैं। 25 अप्रैल 2015 को आए भूकंप के तुरंत बाद, गुरुंग ने सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई। इसके जवाब में करीब 200 स्वयंसेवक जुट गए। उन्होंने गांवों में चावल पहुंचाया, स्कूलों में तंबू लगाए, और उधार की मोटरसाइकिलों पर घायलों को अस्पतालों तक ले गए। इस अस्थायी नेटवर्क ने हमी नेपाल (हम नेपाल हैं) का



रूप लिया, जो 2020 तक 1,600 से अधिक सदस्यों वाला एक पंजीकृत एनजीओ बन चुका था।

अनुशासित और केंद्रित नेतृत्व : प्रसिद्ध नेत्र सर्जन और हमी नेपाल के मेंटर डॉ. संदूक रुइत कहते हैं, सुदन गुरुंग एक असामान्य रूप से अनुशासित ग्रास्रुट लीडर हैं। उनकी ताकत बयानबाजी में नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स पर ध्यान देने में है, यही कारण है कि युवा उन पर भरोसा करते हैं। सोशल मीडिया बैन और जेन जेड का विद्रोह हाल के आंदोलनों ने हमी



नेपाल की इस विरासत को एक राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया। जब नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया, तो जेन जेड को लगा कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। गुरुंग ने स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें हाथ में लेकर सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों ने एक अनोखा प्रतीक चुना- जापानी एनीमे वन पीस का स्ट्रैंड हैट जॉली रोजर झंडा उठाया। यह इस एनीमे के कैरेक्टर मंकी डी. लफी की पहचान है।

इजराइल का कतर की राजधानी दोहा पर हमला: हमारा लीडर बाल-बाल बचे, 6 अन्य की मौत

दोहा, एजेंसी। कतर की राजधानी दोहा में मंगलवार को कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इजराइली सेना ने ऐलान किया कि उसने हमारा के सीनियर नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं। ये हमला हमारा चीफ खलील अल-हय्या को निशाना बनाकर किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमले में अल-हय्या बच गया, जबकि 6 अन्य लोगों की मौत हो गई। इस बीच इजराइली पीएम नेतन्याहु ने भी कहा कि इजराइल इस हमले को 'पूरी जिम्मेदारी' लेता है। जब यह हमला तब हुआ जब हमारा नेता अमेरिका के युद्धविग्राम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे। इजराइली सेना और सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि यह हमला बेहद सटीक तरीके से उन हमारा नेताओं पर किया गया, जो संगठन की गतिविधियों को लंबे समय से चला रहे थे। एसोसिएटेड



प्रेस से बात करते हुए एक इजराइली अधिकारी ने पुष्टि की कि यह हमला कतर की राजधानी दोहा में हुआ। सेना के मुताबिक ये हमारा लीडर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे।

कतर में हमारा नेताओं का ठिकाना : यह हमला ऐसे समय हुआ है जब इजराइली सेना के जनरल स्टाफ प्रमुख इयाल जमीर ने हाल ही में कहा था कि विदेशों में

मौजूद हमारा नेताओं को भी निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने 31 अगस्त को कहा था कि हमारा सा अधिकारश नेतृत्व विदेश में है, और हम उन तक भी पहुंचेंगे। कतर लंबे समय से हमारा के निर्वासित नेताओं का ठिकाना रहा है और वह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। गाजा पर युद्धविग्राम और 7 अक्टूबर को हमारा के बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई को लेकर जो बातचीत चल

रही थी, यह हमला उसे और जटिल बना सकता है।

कतर ने इजराइली हमले की आलोचना की : हमले के बाद कतर ने इजराइल की कड़ी आलोचना की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने इसे हमारा के राजनीतिक मुख्यालय पर कायराना हमला करार दिया और कहा कि यह सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन है। दूसरी ओर, इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने इस कार्रवाई की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को दुनिया में कहीं भी इजराइल से छूट नहीं मिलेगी। एक्स पर लिखते हुए उन्होंने दृढ़ता और शिन बेट के सही फैसले और सटीक निशाने की सराहना की और कहा कि आतंकवादियों को इजराइल के लंबे हाथों से कभी भी काई छूट नहीं मिलेगी।

चीन में टैरिफ से अमेरिकी कंपनियों की बिक्री में आएगी गिरावट, शंघाई चैंबर के सर्वे में बड़ा खुलासा



बीजिंग, एजेंसी। चीन पर अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ को लेकर शंघाई में अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। सर्वे के बाद सामने आया है कि टैरिफ से चीन में काम कर रही कई अमेरिकी कंपनियों की बिक्री प्रभावित होगी। इसमें गिरावट आएगी। सर्वे में भाग लेने वाली 254 कंपनियों में से लगभग दो-तिहाई ने कहा कि नए टैरिफ ने 2025 में उनके चीन परिचालन के लिए अपेक्षित राजस्व को कम कर दिया है। वहीं लगभग एक-तिहाई कंपनियां जिनमें से कई बैंकिंग और अन्य उद्योगों में हैं जो अमेरिका से आयात या निर्यात नहीं करते हैं, उन्हें किसी भी प्रभाव की उम्मीद नहीं है। शंघाई चैंबर के नेताओं ने कहा कि टैरिफ से उन कंपनियों पर असर पड़ेगा जो अमेरिका को निर्यात करती हैं और उन कंपनियों पर भी जो चीन में अपने उत्पादन के लिए अमेरिकी पार्ट्स या सामग्री आयात करती हैं। समूह के अध्यक्ष एरिक झोंग ने कहा कि टैरिफ का हमारे परिचालन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। दोनों पक्ष व्यापार वार्ता कर रहे हैं, लेकिन टैरिफ और अन्य मुद्दों पर उनकी दिशा स्पष्ट नहीं है। यह अनिश्चितता उन कंपनियों के लिए

एक चुनौती है जिन्हें भाविष्य के लिए योजनाएं बनाने की जरूरत है। 19 मई से 20 जून तक किए गए शंघाई चैंबर सर्वेक्षण में पाया गया कि अमेरिकी आयात पर 10 प्रतिशत टैक्स ट्रंप ने चीन से आयात पर 30 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। जबकि मई में दोनों देशों के बीच टैरिफ युद्ध को कम करने पर सहमति बनने से पहले इसे एक समय 145 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था। चीन ने भी अमेरिकी आयात पर 10 प्रतिशत कर लागू कर जवाब दिया है। वहीं अमेरिकी अकालतों ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप के कई टैरिफ अमेरिकी आपातकालीन शक्ति कानून का अवैध उपयोग हैं, लेकिन आयात कर यथावत बने रहेंगे, क्योंकि उनका प्रशासन इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर रहा है।

50 गाड़ियों के काफिले के साथ 'सरदार सम्मान यात्रा' का शुभारंभ

12 दिनों में 1800 किमी की दूरी तय कर 355 गांवों में राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाएगी

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

आजादी के अमृतकाल में राष्ट्रभक्ति और एकता के संदेश को और मजबूत बनाने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल की कर्मभूमि बारडोली से उनकी 150वीं जयंती से पूर्व 'सरदार सम्मान यात्रा-2025' का शुभारंभ हुआ है। 11 सितंबर को बारडोली के ऐतिहासिक स्वराज आश्रम से 50 गाड़ियों के काफिले के साथ इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह यात्रा अगले 12 दिनों में गुजरात के 18 जिलों, 62 तालुकाओं और 355 गांवों को कवर करते हुए 22 सितंबर को पवित्र सोमनाथ धाम पर समाप्त होगी। 'सरदार सम्मान यात्रा' के मुख्य संयोजक गोपालभाई वस्तरपारा

और कृतित्व को श्रद्धांजलि देना है। सरदार साहब ने 562 रियासतों को एक करके अखंड भारत के निर्माण का जो अमूल्य कार्य किया, उससे प्रेरणा लेकर यह यात्रा समाज, संस्थाओं और वर्गों को एकजुट करने का प्रयास करेगी। यह यात्रा कुल 1800 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें 18 जिले और 62 तालुकों के 355 गांव शामिल होंगे। इसके अलावा यह यात्रा लगभग 40 नदियों को भी कवर करेगी, जो सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता का संदेश भी देगी। यात्रा के प्रस्थान के समय स्वराज आश्रम के प्रमुख भीखाभाई, सरदार साहब को करीब से देखने वाली निरंजनाबेन कलारथी के अलावा अमेरिका, लंदन, राजस्थान, हरियाणा और मध्यप्रदेश से आए प्रमुख लोग भी उपस्थित थे।

दिन (13 सितंबर) वडोदरा से हालोल और गोधरा होते हुए आनंद और करमसद पहुंचेगी। इसके बाद आने वाले दिनों में यह यात्रा अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाणा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, गोंडल, शिहोर, भावनगर, पालीताना, दामनगर, अमरेली, सावरकुंडला, जूनागढ़, सासनगर, तालाला, वेरावल होते हुए अंत में 22 सितंबर को सोमनाथ पहुंचेगी। यह यात्रा जिन गांवों और शहरों में रात्रि विश्राम करेगी, वहां जनसभाओं का आयोजन होगा। इन सभाओं में सरदार पटेल के जीवन, आजादी की लड़ाई में उनके योगदान और राष्ट्र निर्माण के कार्यों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। इस यात्रा का समापन 22 सितंबर को सोमनाथ में आयोजित सभा में होगा, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। लसकाणा इलाके के विपुलनगर में एक युवक का कटा हुआ सिर मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस जांच में सामने आया कि जिस स्थान से सिर मिला था, वहां से थोड़ी दूरी पर एक कमरे से धड़ भी बरामद किया गया। मिली जानकारी के अनुसार,



फिलहाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान की जांच कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार, अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। इलाके में रहने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। जिस कमरे से धड़ मिला

है, वह काफी समय से खाली पड़ा था, जबकि सिर कमरे से करीब 200 मीटर दूर बरामद हुआ है। उल्लेखनीय है कि यह घटना लसकाणा पुलिस स्टेशन से महज 400 मीटर की दूरी पर हुई है। इस मामले में डीसीपी आलोक कुमार ने बताया कि मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। इलाके में रहने वाले लोगों को बुलाकर मृतक की पहचान परेड की जा रही है। कमरा लंबे समय से खाली पड़ा था। कमरे के अंदर से शरीर का एक हिस्सा मिला है, जबकि

बलात्कार के आरोपी को 20 साल कैद, पीड़िता को 6 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के अडाजण इलाके में वर्ष 2024 में नवरात्रि के दौरान 12 साल की बच्ची से कई बार जबरन बलात्कार करने वाले 22 वर्षीय आरोपी राहुल उर्फ पुलिस दीपक चौहान को सूरत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भावेश के. अवासिया ने पाँक्सो एक्ट समेत कई अपराधों में दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, अदालत ने आरोपी को 1.75 लाख रुपये का जुर्माना और पीड़िता को 6 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। घटना क्या थी?

घटना नवंबर 2024 में नवरात्रि के चौथे दिन की है। अडाजण इलाके में रहने वाले आरोपी

राहुल चौहान (उम्र 22) ने 12 साल 8 महीने की पीड़ित बच्ची को अपने घर बुलाया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद, उसने किसी को बताने की धमकी देकर बच्ची के साथ एक से ज्यादा बार बलात्कार किया। इस मामले में पीड़ित बच्ची की माँ ने 12 फरवरी 2025 को अडाजण पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

अडाजण पुलिस ने मामले की त्वरित सुनवाई के लिए आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए थे।

सरकारी पक्ष की ओर से एपीपी दीपेश दवे ने 10 गवाह और 29 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। जिनमें पीड़ित लड़की की गवाही, मेडिकल साक्ष्य और अन्य गवाहों की गवाही प्रमुख थी। बचाव पक्ष ने दलील

दी कि इस अपराध में कोई चशमदीद गवाह नहीं था और पीड़िता और आरोपी के बीच दोस्ताना संबंध थे। उन्होंने यह भी दलील दी कि चूँकि घटना के 20 दिन बाद शिकायत दर्ज की गई थी, इसलिए इसमें देरी हुई और एफएसएल रिपोर्ट में कपड़ों पर कोई दाग नहीं पाया गया। हालाँकि, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर गौर करने के बाद आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने कहा कि पीड़िता सिर्फ 12 साल की थी और 22 साल के आरोपी ने यह जानते हुए भी उसके साथ बलात्कार किया।

चूँकि समाज में इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, इसलिए मिसाल कायम करने के लिए आरोपी को कड़ी सजा देना जरूरी है।

रिश्वत मामले में फैसला

नवसारी में 5,000 की रिश्वत लेने वाले GMB के जूनियर क्लर्क को 3 साल की जेल, 10 हजार का जुर्माना

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

नवसारी की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने रिश्वतखोरी मामले में अहम फैसला सुनाया है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (GMB) के जूनियर क्लर्क दिनेश बाबू गविंत को तीन

साल की कैद की सजा सुनाई गई है। मामले के विवरण के अनुसार, 2010 में दिनेश गविंत ने एक मछुआरे से 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत लेते समय वह रंगेहाथ पकड़े गए थे। इस केस में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज पी.जे. तमाकुवाला ने सरकारी वकील

की दलीलों पर गौर किया था। अदालत ने आरोपी दिनेश गविंत को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है। जेल की सजा के अलावा अदालत ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों में हलचल मच गई है।

कोर्ट से फरार हुआ हत्या का आरोपी कुछ ही घंटों में पकड़ा गया

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

वडोदरा क्राइम ब्रांच ने कुछ ही घंटों में हत्या के आरोपी हार्दिक प्रजापति को सूरत से गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार सुबह वडोदरा क्राइम ब्रांच ने सूरत से आरोपी को हिरासत में लिया। यह जांच जारी है कि हार्दिक को भगाने में किसी का हाथ था या नहीं। 9 सितंबर (बुधवार) दोपहर को हार्दिक को सेंट्रल जेल से अदालत की कार्यवाही के लिए दिवालिपुरा कोर्ट



परिसर में लाया गया था। कोर्ट केटीन के पास पानी पीने के बहाने उसने पुलिस को चकमा

देकर फरार हो गया था। हार्दिक पर अपने ही दोस्त की हत्या का आरोप है।

सूरत के रांदेर पुलिस स्टेशन में रंगाई-पुताई का काम करने आए पुलिस स्टेशन में PSI की कुर्सी पर बैठकर फोटोशूट

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के रांदेर पुलिस स्टेशन में रंगाई-पुताई का काम करने आए एक कारीगर ने खुद पुलिस का ही 'कलर' कर दिया। उसने पुलिस स्टेशन में PSI की कुर्सी पर बैठकर फोटोशूट करवाया और इंस्टाग्राम पर यमराज से अपनी यारी है गाने के साथ पोस्ट कर दिया। पोस्ट होते ही हजारों लाइक्स और कमेंट आने लगे। यह कारीगर सोशल मीडिया पर भोला राजभर बाहुबली के नाम से मशहूर है। बाद में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया और वहीं कान पकड़कर माफी मंगवाई, ताकि उसे कानून का एहसास कराया जा सके। युवक का नाम योगेंद्र राज है

और वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी है। कुछ महीने पहले वह रांदेर पुलिस स्टेशन में रंगाई का काम करने गया था। उसी समय उसने PSI की कुर्सी पर बैठकर फोटोशूट करवाया था। युवक सोशल मीडिया पर काफी मशहूर है और उसके इंस्टाग्राम पर 16.50 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। PSI की कुर्सी पर बैठे फोटो को 1400 से ज्यादा लाइक्स और 36 कमेंट मिले थे, जिनमें उसने यमराज से अपनी यारी है गाना भी जोड़ा था।

चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले यही युवक शराब के नशे में पकड़ा गया था और रांदेर पुलिस उसे थाने लाई थी। पुलिस के अनुसार, उस समय उसने अपना नाम बताते से इनकार कर दिया था और थाने में गाली-गलौच की थी। उसने यह दावा भी किया था कि

उसके रंगाई के पैसे बकाया हैं। उस समय उसकी एंटी पुलिस रिकॉर्ड में की गई थी। शराब के नशे में पकड़े जाने का वीडियो भी अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हालाँकि यह वीडियो 4 दिसंबर 2024 का था, लेकिन अब लोगों का ध्यान खींच रहा है। पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी ने सिर्फ रांदेर पुलिस स्टेशन में ही नहीं बल्कि रेलवे पुलिस चौकी के बाहर भी फोटोशूट कर तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली थीं। आरोपी ने कान पकड़कर स्वीकार किया कि 6-7 महीने पहले वह रंगाई का काम करने रांदेर थाने गया था और उसी समय उससे गलती हुई थी। वीडियो वायरल होने के बाद रांदेर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है

दही-हांडी कार्यक्रम के दौरान मटकी फोड़ते समय नीचे गिरकर

गंभीर रूप से घायल हुए 21 वर्षीय युवक जयसिंह की इलाज के दौरान मौत

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत की सिविल अस्पताल फिर एक बार विवादों में धिर गई है। दही-हांडी कार्यक्रम के दौरान मटकी फोड़ते समय नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए 21 वर्षीय युवक जयसिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने इस मौत के लिए अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। परिवार का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद जयसिंह की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन डॉक्टरों ने लापरवाही बरती और उसे ड्रष्ट में भर्ती करने में आनाकानी की।

मूल रूप से उत्तर प्रदेश निवासी और सूरत में ITI में पढ़ाई कर रहे 21 वर्षीय जयसिंह दही-हांडी फोड़ते समय नीचे गिर गए थे। इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें तुरंत सूरत की सिविल अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि उनके सिर की नस ब्लॉक हो गई है और तुरंत ऑपरेशन करने का फैसला लिया। परिवार के मुताबिक, जयसिंह का ऑपरेशन 26 तारीख को

किया गया था। 27 तारीख तक हालत ठीक थी, लेकिन 28 तारीख को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। जब परिवारजन डॉक्टरों को बुलाने गए तो वे अपने चेंबर में सो रहे थे। पूछने पर डॉक्टरों ने कहा- इतना तो होता रहता है जज और जिम्मेदारी टाल दी। इसके बाद जयसिंह को आंक्सिजन पर



रखा गया। जयसिंह के पिता शत्रुघ्न सिंह और दोस्त मनीष ने गंभीर आरोप लगाए कि ड्रष्ट में जगह न होने का हवाला देकर पहले भर्ती करने से इनकार किया गया। दबाव डालने के बाद 29 तारीख को उन्हें ड्रष्ट में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां भी डॉक्टरों की लापरवाही जारी रही। ड्रष्ट में सिर्फ एक व्यक्ति को जाने की अनुमति थी और जब भी कोई शिकायत की जाती, तो डॉक्टर अभद्र व्यवहार करते और जिम्मेदारी

लेने से बचते। जयसिंह के पिता शत्रुघ्न सिंह ने कहा- कल जब नली बदली गई, तो डॉक्टर ने कहा कि बेटे ने अपने दांतों से नली काट दी थी। मेरा बेटा तो हिल भी नहीं पा रहा था, तो वह नली कैसे काट सकता था? यह सीधी लापरवाही टाल का मामला है। इस मामले पर सूरत सिविल

अस्पताल के CMO केतन नायक ने कहा कि फिलहाल उन्हें पूरे मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जाएगी। जयसिंह अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। उसके पिता लूमस कारखाने में नौकरी कर घर चलाते हैं। परिवार में जयसिंह के अलावा एक बहन और एक छोटा भाई भी है। जयसिंह की आकस्मिक मौत से पूरा परिवार सदमे में है और न्याय की मांग कर रहा है।



बढ़ गया है। किसानों को चिंता है कि यदि यह स्थिति जारी रही तो चीकू का उत्पादन देर से होगा। फरवरी से अप्रैल के दौरान जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा,

पानी का जमाव बड़ी समस्या है। खेतों से पानी निकलना चाहिए, लेकिन वह नहीं निकलता जिससे फसल को नुकसान होता है।